शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 29 | गुवाहाटी | रविवार, 30 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

नवी मुंबई में फोटोकॉपी की शॉप से 3,404 एसआईआर फॉर्म बरामद, पांच... पेज 2
कोकराझाड़ में बीवीसी और बीएमसी की संयुक्त बैठक संपन्न पेज 3
पंजाब सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को भेजे नोटिस, कर्मचारी पहुंचे ... पेज 5
एशियाई खेलों में पदक का रंग बदलना चाहती हैं आशी चौकसे... पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए।
- आचार्य चाणक्य

नेपाल के सैलाब ने बढ़ाई भारत की टेंशन, हिमालय क्षेत्र की 200 ग्लेशियल झीलों पर मंडराया खतरा, 25 अतिसंवेदनशील

नई दिल्ली। बुधवार को नेपाल में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियल झील फटने से आई अचानक बाढ़ की घटना ने भारत को अपनी रणनीति और तैयारियों पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 200 ऐसी ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं, जिनसे भविष्य में अत्यधिक खतरा हो सकता है और इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार, हिमालयी रेंज में कुल मिलाकर लगभग 7,500 ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। इनमें से 10 प्रतिशत झीलें केवल सिक्किम में स्थित हैं और वहां की 25 झीलों को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि इन कुल झीलों में से 4,700 ग्लेशियल झीलें गंगा नदी बेसिन में आती हैं, जिनका कैचमेंट एरिया 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी एक भी झील का प्राकृतिक बांध टूटता है, तो मैदानी और निचले इलाकों में कितनी भयानक तबाही मच सकती है। हाल ही के

समय में भारत ने जीएलओएफ से जुड़ी सबसे भीषण आपदाओं में से एक का सीधा सामना किया था। 3 अक्तूबर 2023 की आधी रात के करीब सिक्किम की साउथ ल्होनक झील में ग्लेशियल चट्टानों का एक बहुत विशाल हिस्सा लगभग 14.7 मिलियन क्यूबिक मीटर अचानक ढह गया था। इसके कारण झील से 20 मीटर ऊंची एक विनाशकारी लहर उठी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली कई पनबिजली परियोजनाओं और बस्तियों को पूरी तरह से बहा दिया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य कृष्णा वत्सा का कहना है कि नेपाल की घटना हिमालयी आपदाओं के एक नए और जटिल पहलू को दर्शाती है। हालांकि, इस घटना के वैज्ञानिक कारणों की अभी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसे खतरे अक्सर एक चेन रिएक्शन की तरह होते हैं। बर्फ या चट्टान गिरने से मलबा बहता है, जिससे एक अस्थायी झील बन जाती है और फिर वह अचानक फटकर बाढ़ का रूप ले लेती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने का बहुत कम समय मिल पाता है। -शेष पृष्ठ दो पर

सज्जन कुमार के घर जाने वाले तीन भाजपा सांसदों पर पार्टी सख्त

नई दिल्ली (हि.स.)। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके घर शोक व्यक्त करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन सांसदों पर पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों सांसदों को तलब कर उनके इस कदम पर नाराजगी जताई और कड़ी फटकार लगाई। फटकार पाने वाले सांसदों में दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया और पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत शामिल हैं। इस घटनाक्रम पर 1984 सिख दंगा पीड़ितों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ नेता एच.एस. फुल्का ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए एक्स पर कहा कि वे तीन सांसदों-कमलजीत -शेष पृष्ठ दो पर

असम सरकार के 100 दिन

विकास, सुशासन और जनकल्याण को भाजपा ने बताया उपलब्धियों का नया अध्याय

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार के पहले 100 दिनों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विकास, सुशासन और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का कालखंड बताया है। भाजपा, असम प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट दिलीप कुमार शर्मा ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन से जारी बयान में कहा कि सरकार ने चुनावी संकल्पों को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से काम किया है। दिलीप कुमार शर्मा ने कहा कि इन 100 दिनों में कानून-व्यवस्था, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, कृषि, उद्योग और ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा सशक्तिकरण एवं विकास विभाग का गठन किया गया, जबकि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अरुणोदय 3.0 शुरू किया गया, जिससे 37 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत 78,490 माताओं को डीबीटी के माध्यम से 23.26 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। बालिका शिक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए निजुत मोइना योजना में 5.16 लाख छात्राओं को शामिल किया गया है। वहीं, उच्च शिक्षा के लिए निजुत बाबू योजना शुरू की गई है, जिससे 99 हजार से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य क्षेत्र में गौहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसमें आईसीयू क्षमता बढ़ाने के साथ अस्पताल की कुल बिस्तर क्षमता 4,500 करने की पहल शामिल है। भाजपा के अनुसार, असम का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 84 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। शिक्षा के क्षेत्र में आईआईएम गुवाहाटी के प्रथम वर्ष के एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। इसके अलावा दो इंजीनियरिंग कॉलेज, टिंगखांग पॉलिटेक्निक और दो मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण पूरा होने की जानकारी दी गई। कृषि क्षेत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान पर 200 रुपए और सरसों पर 300 रुपए अतिरिक्त देने के सरकार के निर्णय का भी उल्लेख किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विद्यार्थियों की भागीदारी से पूरे राज्य में 1.5 करोड़ पौधों के रोपण को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया गया। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा नेता ने कहा कि अगले पांच वर्षों में दो लाख युवक-युवतियों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति देने की घोषणा की गई है। साथ ही 200 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दिलीप कुमार शर्मा ने हाल में ऊपरी असम के चार जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री ने रिक्त पदोन्नति पदों को भरने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय की

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में पदोन्नति पदों के रिक्त पड़े होने की स्थिति को देखते हुए सभी वरिष्ठतम सचिवों को इस मामले की समीक्षा करने और पंद्रह दिनों के भीतर सभी पदोन्नति पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने एक पत्र में कहा कि नियमों के तहत जहां भी अनुमति हो, योग्यता, उपयुक्तता या नियुक्तियों की गुणवत्ता से समझौता किए बिना, आयु, अनुभव या अन्य पात्रता मानदंडों से संबंधित आवश्यकताओं में उचित रूप से ढील दी जा सकती है। कई मामलों में, एसीआर की अनुपलब्धता, निर्धारित न्यूनतम वर्षों की सेवा या कार्य अनुभव की कमी, लंबित विभागीय कार्यवाही, सतर्कता मामलों और अन्य प्रशासनिक कारणों से पदोन्नति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के पदों का न भरा जाना न केवल विभागों के कामकाज में असुविधा पैदा करता है, बल्कि इससे संबंधित -शेष पृष्ठ दो पर

भाजपा ने युवाओं को साधने की रणनीति पर की बड़ी बैठक

नई दिल्ली (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश की नई युवा पीढ़ी यानी जेन-जी तक अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार कर आगे की कार्ययोजना बनाने के लिए शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अलग-अलग राज्यों से करीब 45 नेता पहुंचे। बैठक में मौजूद रहने वाले प्रमुख नेताओं में राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, -शेष पृष्ठ दो पर

सीएम ने असम रेजिमेंटल सेंटर का दौरा कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

शिलांग। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 29 अगस्त को शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में शिलांग में स्थापित असम रेजिमेंटल सेंटर, भारतीय सेना की असम रेजिमेंट का मुख्यालय है। दिसपुर के राज्य की स्थायी राजधानी बनने के बाद से यह पहली बार था जब किसी असम के मुख्यमंत्री ने इस केंद्र का दौरा किया। इससे पहले केवल पूर्व मुख्यमंत्री बिष्णुराम मेधी और बिमला प्रसाद चालिहा ने ही इस केंद्र का दौरा किया था, इसलिए शर्मा का यह दौरा एक महत्वपूर्ण अवसर था। अपनी यात्रा के दौरान, शर्मा ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए और ड्रोन से संबंधित युद्ध रणनीतियों, जंगल में गोलीबारी, कमांडो प्रशिक्षण, आदिवासी जाल अभ्यास और रिफ्लेक्स शूटिंग रेंज सहित विभिन्न प्रदर्शनों का अवलोकन किया। सेना के जवानों ने मार्शल आर्ट और कराटे का प्रदर्शन करते हुए अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के दाह सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां असम रेजिमेंट के इतिहास पर आधारित एक वृत्तचित्र दिखाया -शेष पृष्ठ दो पर

नेपाल बाढ़ राहत कोष में 2.29 अरब रुपए से अधिक दान मिला

काठमांडु। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मची भारी तबाही के बाद देश के प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं और गत तीन दिन में 2.295 अरब रुपए से अधिक का दान मिला है। नेपाल में गत बुधवार को आई अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है। इस बाढ़ ने कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, जिससे घर, गाड़ियां, सड़कें और पुल बह गए तथा पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा एवं अब भी करीब 2,400 लोग लापता हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने -शेष पृष्ठ दो पर

केरलम में कांग्रेस नेता ने रोका सीएम का काफिला, हुई तीखी बहस

तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में शुक्रवार को उस समय अजीब स्थिति बन गई जब अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन का काफिला रोक दिया। समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे सतीशन और तिरुवनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के नेता अनिल कुमार, चेंथी अनी, के बीच सड़क पर ही तीखी बहस हो गई। इस पूरे -शेष पृष्ठ दो पर

प्रणब दोले की एनएसए हिरासत को लेकर गौहाटी एचसी ने केंद्र और राज्य को भेजा नोटिस

गुवाहाटी। गौहाटी उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत स्वदेशी अधिकार कार्यकर्ता प्रणब दोले की निवारक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फुकन खाउंद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. बरठाकुर और उनके साथ उपस्थित अधिवक्ताओं, जिनमें दीपेश कुमार अग्रवाल भी शामिल थे, की दलीलें सुनने के बाद 27 अगस्त को यह आदेश पारित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर गौहाटी उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और असम गृह एवं राजनीतिक विभाग को दोले की हिरासत की वैधता -शेष पृष्ठ दो पर

एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान- आतंकवाद पूरी तरह हो खत्म

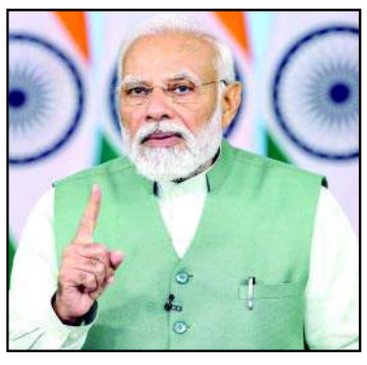

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की दो देशों की यात्रा पर रवाना हुए। वे एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस संगठन के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और आतंकवाद के खतरे से मुक्त क्षेत्र के लिए साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं। मोदी पहले उज्बेकिस्तान (29-30 अगस्त) जाएंगे और फिर बिश्केक, किर्गिज गणराज्य (30 अगस्त-1 सितंबर) में समिट में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी यह यात्रा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी और इस क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेगी। रवाना होने से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि यह यात्रा शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा कोशिशों को आगे बढ़ाएगी; ये मूल्य दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2017 से एससीओ का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य रहा है। मैं सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को -शेष पृष्ठ दो पर

दो दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री

ताशकंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने दो देशों के दौरे के पहले चरण में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत -शेष पृष्ठ दो पर

ममता पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के छात्र संगठन तृणमूल छात्र परिषद के आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 28 अगस्त को संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल समर्थकों ने कथित तौर पर बैरिकेड हटा दिए और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। इसके अलावा कैथेड्रल रोड पर यातायात भी बाधित हुआ। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम अदालत की ओर से तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी जारी रहा। मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61(2), 223, 125(ए), 132 और 285 के तहत दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को अपने समर्थकों से राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकने और भाजपा में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने अपनी पार्टी की छात्र इकाई तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

नवी मुंबई में फोटोकॉपी की शॉप से 3,404 एसआईआर फॉर्म बरामद, पांच बीएलओ सस्पेंड

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े 3,404 फॉर्म की फोटोकॉपी किए जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद पांच बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी फॉर्म पनवेल विधानसभा क्षेत्र के थे और इनमें मतदाताओं की तस्वीर, निजी जानकारी और बीएलओ के आधिकारिक हस्ताक्षर मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब शिवसेना (यूबीटी) के एक स्थानीय नेता ने खारघर की एक दुकान में भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के पदाधिकारी सूरज पाटिल को पनवेल विधानसभा क्षेत्र के 3,404 एसआईआर फॉर्म के साथ पकड़ा। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई की एक दुकान में भाजपा के एक स्थानीय कार्यकर्ता को मतदाताओं की जानकारी वाले 3,000 से ज्यादा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) चुनावी फॉर्म की फोटोकॉपी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद पांच बूथ-लेवल अधिकारियों (बीएलओएस) को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और रेवेन्यू अधिकारियों ने जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई और सूरज पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जब्त किए गए दस्तावेजों में 188 पनवेल विधानसभा क्षेत्र के असली एसआईआर फॉर्म शामिल थे, जिनमें मतदाताओं की तस्वीरें, निजी जानकारी और बीएलओ के आधिकारिक हस्ताक्षर थे। इस मामले में रायगढ़ कलेक्टर ने कहा कि हमारे अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि वे वास्तव में असली थे और उनकी जिम्मेदारी बीएलओ की थी। इसलिए, हमने उस इलाके के पांच बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। वहीं खारघर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पाटिल को हिरासत में लिया गया और रिहा करने से पहले मानक कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद प्रशासन ने इस बात की जांच की कि आखिर मतदाताओं द्वारा भरे गए एसआईआर फॉर्म एक निजी फोटो कॉपी सेंटर तक कैसे पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची और भाजपा पदाधिकारी को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने दुकान से बड़ी तादाद में प्रिंट किए गए एसआईआर फॉर्म भी जब्त किए और उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया। इस मामले को लेकर शिवसेना (यूबीटी) और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि, पनवेल नगर निगम के महापौर और भाजपा नेता नितिन पाटिल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा कि पांच बीएलओ को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना ने एसआईआर प्रक्रिया के संचालन के तरीके में खामियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि हम कहते आ रहे हैं कि भाजपा इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए कर रही है और यह घटना हमारी बात को सही साबित करती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से भी सवाल किया गया, लेकिन वहां से जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर भेज दी गई। उन्होंने कहा कि केवल बीएलओको निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें निर्देश देने वाले अधिकारियों को भी निलंबित किया जाना चाहिए और इसमें शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की कई घटनाएं हो सकती हैं जिनका पता नहीं चला है।

नेपाल में गौहाटी विवि की सेवानिवृत्त प्रोफेसर और उनके पति लापता

गुवाहाटी (हिंस)। नेपाल में आज जल प्रलय में गौहाटी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. दिपाली सरकार और उनके पति मानस घोष के लापता होने से गहरी चिंता फैल गई है। शहर के जालुकबारी लंकेश्वर इलाके के बसेरा रेजिडेंसी में रहने वाले इस दंपती से 20 अगस्त के बाद से परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहपाठियों का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. दिपाली सरकार और उनके पति कोलकाता के एक टूर एंड ट्रैवल ग्रुप के माध्यम से 32 सदस्यीय दल के साथ नेपाल के रास्ते तिब्बत स्थित कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। हावड़ा की एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए उनकी इस यात्रा की योजना बनाई गई थी। वे 20 अगस्त तक दिल्ली में थे और वहीं से अपनी यात्रा के लिए रवाना हुए थे। काठमांडू पहुंचने के दौरान उनकी परिवार से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उसी अपार्टमेंट में रहने वाली उनकी सहेली कुंतला पात्र ने बताया कि डॉ. दिपाली सरकार की बेटी वर्तमान में दिल्ली के आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चिकित्साविज्ञान की पढ़ाई कर रही हैं। दंपती के लापता होने की खबर फैलते ही पड़ोसियों और स्थानीय निवासियों में भी चिंता बढ़ गई है। परिवार और दोस्तों को आशंका है कि नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ और जलभराव के कारण वे कहीं फंस गए हो सकते हैं। उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए असम सरकार और भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की गई है। डॉ. दिपाली सरकार ने वर्ष 2025 में गौहाटी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्ति ली थी। उनके लापता होने की इस घटना से पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। इस बीच, नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल में अभी भी कुल 178 भारतीय नागरिकों के लापता होने की खबर है।

पोचागढ़ रामकृष्णपारा में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन

कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ जिले के फकीराग्राम नगर क्षेत्र अंतर्गत पोचागढ़ रामकृष्णपारा में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति योजना का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। फकीराग्राम नगरपालिका के अध्यक्ष सुल्तान आलम ने योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पहल से क्षेत्रवासियों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। उद्घाटन समारोह में नगरपालिका के उपाध्यक्ष प्रणव शर्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कोकराझाड़-1 डिवीजन के अभियंता मनोज नंदी, सीएसबी सदस्य एवं समाजसेवी प्रबीर सान्याल, वार्ड सदस्य परिमल धर एवं राजीव सरकार, ठेकेदार अब्दुल रहीम सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि पेयजल आपूर्ति योजना पोचागढ़ रामकृष्णपारा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के माध्यम से घर-घर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा मिलने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने इस विकासात्मक पहल का स्वागत करते हुए फकीराग्राम नगरपालिका एवं संबंधित विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

गोलाघाट में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गोलाघाट (हिंस)। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को गोलाघाट स्थित एक सरकारी विद्यालय में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की पहली बटालियन की *एफ* कंपनी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रथम बटालियन एसएसबी, सोनापुर के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान *एफ* कंपनी, गोलाघाट के सहायक कमांडेंट एवं कंपनी कमांडर आई जमीर ने विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों तथा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थों से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। साथ ही, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सामूहिक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का समापन नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। उधर अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को प्रथम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), सोनापुर के वाहिनी मुख्यालय परिसर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वाहिनी के कमांडेंट सुनील कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में *बी* कंपनी और *डी* कंपनी की टीमें आमने-सामने हुईं।

आंध्र प्रदेश : तीन साल के बच्चे को पुल पर अकेला रोता छोड़ पति-पत्नी ने लगाई गोदावरी नदी में छलांग, तलाश जारी

अमरावती। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में चिंचिनादा वशिष्ठ पुल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गुरुवार रात 29 वर्षीय डोड्डा साई और उनकी 28 वर्षीय पत्नी शिरीशा ने अपने 3 साल के मासूम बेटे को अकेला छोड़कर उफनती गोदावरी नदी में छलांग लगा दी। बच्चे को अकेला रोता देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद बच्चे को परिजनों को सौंप दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से परेशान थे। पुलिस और स्थानीय बचाव दल तैराकों और नाव टीमों के साथ मिलकर नदी में दंपती की तलाश में जुटी हुई है। खबर लिखे जाने तक दंपती का पता नहीं चला था। पुलिस के अनुसार, दंपती अपने छोटे बच्चे के साथ रात करीब 10 बजे स्कूटर पर पुल पर पहुंचे। दंपती ने बच्चे को स्कूटर पर ही अकेला छोड़ दिया और फिर उफनती गोदावरी नदी में कूद गए। तीन साल के मासूम बच्चे को अंधेरे और ठंड के बीच पुल पर अकेला छोड़ दिया गया था। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब बच्चे को रोते हुए देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्चा रोते हुए बार-बार *अम्मा... नन्ना* (मां... पिता) पुकार रहा था, जिसे सुनकर स्थानीय लोग उसके माता-पिता की खोजबीन में जुट गए। जल्द ही सभी को समझ आ गया कि माता-पिता बच्चे को पुल पर अकेला छोड़कर चले गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे को अपनी सुरक्षा में लिया और मौके पर मौजूद स्कूटर को जब्त कर लिया। बाद में बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया। शुरुआती जांच से पता चला है कि पति पेशे से ड्राइवर था और आंध्र प्रदेश लौटने से पहले उन्होंने कुछ समय खाड़ी (गल्फ) देशों में भी काम किया था। पुलिस के अनुसार, माना जा रहा है कि यह परिवार लगातार बढ़ते कर्ज और गंभीर आर्थिक तंगी से परेशान था। जांचकर्ताओं को आशंका है कि इसी आर्थिक तंगी के कारण दंपती को अपना घर बेचने का फैसला लेना पड़ा होगा। हालांकि, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय संकट को ही इस घटना की एकमात्र वजह नहीं माना है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़ी तमाम परिस्थितियों और कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

पृष्ठ एक का शेष

नेपाल के सैलाब ने बढ़ाई ...

वहीं, एनडीएमए के पूर्व सदस्य सैयद सफी अहसान रिजवी के अनुसार, भारत के नेशनल जीएलओएफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम ने खतरे वाली 195 झीलों की पहचान की है। उनका मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस कार्यक्रम की पांच मुख्य प्राथमिकताओं आकलन, निगरानी, शुरुआती चेतावनी, खतरा कम करने और सामुदायिक जागरूकता पर तुरंत और बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। सिक्किम आपदा के बाद केंद्र सरकार ने जीएलओएफ के खतरों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कई एजेंसियों के साथ मिलकर संवेदनशील झीलों का सर्वेक्षण करना और ज्यादा जोखिम वाली झीलों की पहचान करना था। इसके साथ ही, सरकार ने हिमालय के उन चार राज्यों के लिए नेशनल जीएलओएफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के तहत 150 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं, जहां ग्लेशियल झीलों का खतरा सबसे ज्यादा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) समन्वय समिति की नवंबर 2024 में हुई पहली बैठक में आकलन, निगरानी और जोखिम कम करने के उपाय वाले त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर सहमति बनी थी। इससे पहले सरकार ने यह भी जानकारी दी थी कि सभी ए-कैटेगरी की झीलों का आकलन करने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में एनडीएमए, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी-डैक, आईटीबीपी और सेना के वैज्ञानिक एवं अधिकारी शामिल रहे हैं। इन समितियों ने नियमित बैठकें करके फीडबैक लिया, जिसे राज्यों और केंद्र की संयुक्त रणनीति का हिस्सा बनाया गया। हालांकि, इस दिशा में जमीनी स्तर पर आगे की गई कार्रवाई के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

विकास, सुशासन और ...

का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रही और बचाव एवं राहत कार्यों को तेजी से संचालित किया। अब प्रभावित लोगों के दीर्घकालिक पुनर्वास और स्थायी क्षतिपूर्ति के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये 100 दिन केवल समय की गणना नहीं, बल्कि संकल्प, सुशासन, उपलब्धियों और परिवर्तन के 100 दिन हैं। उनके अनुसार, महिला सशक्तिकरण, युवा अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और आपदा के समय जनसेवा के माध्यम से सरकार ने अधिक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार असम के निर्माण की दिशा तय की है।

मुख्यमंत्री ने रिक्त पदोन्नति...

प्रवेश स्तर के पदों पर सीधी भर्ती भी नहीं हो पाती है। परिणामस्वरूप, सरकारी पदों पर भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि प्रवेश स्तर के पदों पर कार्यरत अधिकारी निर्धारित कैरियर संरचना के भीतर उच्च स्तर तक प्रगति करने में असमर्थ हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी पदों के लिए दो लाख से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती करने का वादा किया है। अतः सभी पात्र पदोन्नति पदों को भरने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना अनिवार्य है ताकि परिणामस्वरूप रिक्त होने वाले प्रवेश स्तर के पदों पर सीधी भर्ती की जा सके। यदि एसीआर उपलब्ध नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी से विशेष रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती हैं, उन्होंने निर्देश दिया। शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी परिहार्य प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अगले 15 दिनों के भीतर यथासंभव सभी पात्र पदोन्नति पदों को भरा जाए। सभी पात्र और योग्य अधिकारियों की पदोन्नति के बाद, प्रत्येक विभाग इस नोट के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में तीन सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को आगे की उचित कार्रवाई के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, पत्र में आगे कहा गया है।

भाजपा ने युवाओं को ...

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय युवा एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, बांसुरी स्वराज, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, गुरु प्रकाश पासवान, हेमांग जोशी, योगेन्द्र चंदोलिया, राजू बिस्टा, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत कई युवा नेता एवं पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में देशभर के युवाओं को संगठन से जोड़ने, युवाओं को संगठन में आगे बढ़ाने, नए राजनीतिक आयामों पर विचार-विमर्श करने और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा की गई। युवाओं की बदलती सोच, उनकी पसंद-नापसंद, उनकी परेशानियों और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों को समझने सहित कई प्रमुख बिंदुओं पर भी बैठक में चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए भाजपा यह जानने की कोशिश करेगी कि आज का युवा देश और राजनीति को किस नजर से देख रहा है। भाजपा आने वाले समय में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष अभियान और कार्यक्रमों पर भी जोर दे सकती है।

सीएम ने असम रेजिमेंटल...

गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल थीं, जिनमें बिहू नृत्य और पूर्वोत्तर के योद्धाओं की युद्ध परंपराओं का प्रदर्शन शामिल था। शर्मा ने अधिकारियों, सेना कर्मियों, 24 अग्निवीरों के परिवारों और 20 पूर्व सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने केंद्र के संचालन और वर्तमान स्थिति के बारे में केंद्र कमांडेंट ब्रिगेडियर विकास राय संदिल्या से भी चर्चा की। इस दौरे के दौरान 101 क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वधवा भी उपस्थित थे। देश की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करते हुए शर्मा ने कहा कि उनका अदम्य साहस, वीरता और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने रेजिमेंट के इतिहास को *वीरता और बलिदान* का इतिहास बताया और इस यात्रा को *अत्यंत सम्मान की बात और एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुभव* कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सैनिकों का साहस ही हमारे राष्ट्र की सच्ची शक्ति है। उनका सर्वोच्च बलिदान हम सभी की सामूहिक स्मृति में अमर रहेगा।

नेपाल बाढ़ राहत कोष...

बताया कि बुधवार दोपहर से गुरुवार आधी रात तक 36 घंटों के भीतर कोष में लोगों ने 1.91 अरब रुपए का दान दिया जबकि अकेले शुक्रवार को 38.55 करोड़ रुपए की सहायता राशि जमा हुई। उन्होंने कहा कि हालिया योगदान के साथ कोष में जमा राशि 2.17 अरब रुपए से बढ़कर 4.09 अरब रुपए हो गई है। सरकार ने कोष में दान एकत्र करने और सहायता में समन्वय के लिए वित्त मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष के मद में दिए जाने वाले दान को 10 अलग-अलग वाणिज्यिक बैंकों में मौजूद खातों में जमा कराया जा रहा है। वित्त विभाग सचिवालय के अनुसार, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले संस्थागत दानदाताओं से एक करोड़ रुपए या उससे अधिक का योगदान व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर रहे हैं। इसने यह भी कहा कि व्यक्तिगत दानकर्ता मंत्रालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर नकद योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों ने भी आपदा राहत कोष में एक महीने का वेतन दान करने का फैसला किया है। यह निर्णय शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

केरलम में कांग्रेस नेता...

घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अनिल कुमार को हिरासत में ले लिया है। सामने आए वीडियो में लोगों का ग्रुप सतीशन की गाड़ियों को रोकता दिख रहा है। सतीशन चेम्पाझंथी में एक जयंती कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले चेंथी इलाके में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी श्री नारायण गुरु का कार्यक्रम आयोजित किया था और वे चाहते थे कि सतीशन वहां जरूर रुकें। काफिला रुकने के करीब 30 सेकेंड बाद सतीशन गाड़ी से उतरे और अनिल कुमार से बात करने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ मिनटों की बहस के बाद सतीशन वापस गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। बाद में सतीशन के ऑफिस ने सफाई दी कि चेंथी का कार्यक्रम उनके आधिकारिक तय शेड्यूल में नहीं था। श्रीकार्यम पुलिस ने अनिल कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें रास्ता रोकना, आपराधिक धमकी और सरकारी काम में बाधा डालना शामिल है। एफआईआर के अनुसार, अनिल ने मुख्यमंत्री का आक्रामक तरीके से सामना किया और पूछा कि तय होने के बावजूद वे कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे। जब उन्हें शांत रहने को कहा गया तो उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो आप क्या कर लेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी में भी रुकावट डाली। दूसरी ओर, अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त अनिल कुमार ने सीएम का काफिला रोकने के आरोप से साफ इनकार किया। उन्होंने सतीशन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सड़क पर कॉलेज के छात्रों जैसी हरकत की। अनिल ने सीधे तौर पर कहा कि यह सब पार्टी के भीतर जारी गुटबाजी का नतीजा है। आयोजकों ने सतीसन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी जारी की, जिसमें वे उन्हें न्योता देते दिख रहे हैं। वहीं, डीसीसी सदस्य सुहैल शाहजहां ने अनिल की गिरफ्तारी पर दुख जताते हुए कहा कि अनिल जैसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं ने कोई गाड़ी नहीं रोकी थी, वे बस स्वागत के लिए खड़े थे।

प्रणब दोले की एनएसए ...

की जांच करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी, अगरवाला ने कहा। असम ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, दोले को शुरू में 12 जुलाई को बोकाखाट पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले संख्या 108/2026 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जो भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। गोलाघाट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बाद में 29 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, जमानत आदेश के अनुसार उन्हें रिहा किए जाने से पहले, राज्य ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) लागू कर उन्हें निवारक हिरासत में रख दिया। यह नजरबंदी आदेश 30 जुलाई को असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी किया गया था। सरकार का कहना था कि दोले की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हानिकारक थीं, और रिहा किए जाने पर उसके द्वारा ऐसी गतिविधियों को जारी रखने की संभावना थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में निवारक हिरासत की वैधता को चुनौती दी गई है। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कहा कि मुख्य तर्क यह है कि एनएसए, एक असाधारण निवारक कानून होने के नाते, सामान्य आपराधिक कार्यवाही के विकल्प के रूप में मात्र इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नाम न छापने की शर्त पर उस व्यक्ति ने कहा कि अधिकारियों ने यह साबित करने में विफल रहे हैं कि दोले की गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था को किस प्रकार का खतरा था जिसके लिए निवारक हिरासत की आवश्यकता थी। याचिका में आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि दोले को आपराधिक मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, इसलिए सामान्य आपराधिक कानून प्रक्रिया पहले से ही चल रही होने के बावजूद उसे हिरासत में रखने के लिए निवारक हिरासत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अभी तक इन मुख्य आपत्तियों पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। उसके नवीनतम आदेश में केवल याचिका का संज्ञान लिया गया है और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह ताजा कार्यवाही गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा दोले की हिरासत के दौरान उसके परिवार और कानूनी वकील से मिलने के अधिकार के संबंध में किए गए पूर्व हस्तक्षेप के बाद हुई है। 7 अगस्त के एक आदेश में, अदालत ने दोले के पिता लखी दोले द्वारा दायर एक याचिका पर विचार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें, उनके एक मित्र और दोले के वकील के साथ, गोलाघाट जिला जेल में बंदी से मिलने से रोका गया था। अदालत ने गौर किया कि जिला मजिस्ट्रेट और जेल अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। अदालत ने माना कि परिवार के सदस्यों से मिलने और वकील से परामर्श करने का बंदी का अधिकार अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा का हिस्सा है।

एससीओ शिखर सम्मेलन से ...

आगे बढ़ाने और आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खतरे से मुक्त क्षेत्र के लिए साथी सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हूं। ये खतरे हमारे पड़ोस और उससे आगे शांति और स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वे 29-30 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के लिए ताशकंद जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने तथा *विकसित भारत* और *यांगी उज्बेकिस्तान* (नया उज्बेकिस्तान) के हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री मेमोरियल और महात्मा गांधी सेंटर भी जाएंगे। यह हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले करीबी सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ताशकंद से किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक जाएंगे। वहां वे 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो इस अहम संगठन के 25 साल पूरे होने का मौका है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति झापारोव और एससीओ के दूसरे नेताओं से मिलने और छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। यह मध्य एशिया की समृद्ध जीवित विरासत का जश्न है, जिसका भारत बहुत सम्मान करता है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें वे सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों के मामले में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

दो दिवसीय दौरे पर ...

किया गया। पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान का यह चौथा दौरा है। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत-उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन-जन के बीच आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में काफी प्रगति हुई है। मैं राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान (नया उज्बेकिस्तान) के साझा विजन को आगे ले जाने पर चर्चा के लिए उत्सुक हूं। ताशकंद प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी शास्त्री मेमोरियल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा, वह ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज स्थित महात्मा गांधी सेंटर भी जाएंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री मोदी किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सादिर झापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक के लिए रवाना होंगे। वहां वह 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन एससीओ संगठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

ममता पर हाईकोर्ट के ...

दिवस कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द ही सत्ता में वापस आएगी और एक नया राजनीतिक इतिहास लिखेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने साथियों से कहती हूं कि मजबूत और निडर बने रहें। जरूरत पड़े तो एक महीने तक जेल का खाना खाएं, लेकिन राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण न करें। उन्होंने पार्टी के युवा समर्थकों से कहा कि तृणमूल कांग्रेस ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जैसे लोग, जो छात्र राजनीति से उठकर सत्ता तक पहुंचे हैं, उन्हें डराया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। विपक्ष और अन्य वर्गों की ओर से लंबे समय से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र के बड़े हिस्से में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। अधिकारी ने जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा कि छात्र संघ चुनाव जल्द होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर जगह जीत हासिल करेगी। कॉलेजों में भगवा झंडे लहराएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा छात्र संगठन है। विपक्षी दल लगातार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। हाल में कई उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों के बीच हुई झड़पों के बाद यह मांग एक बार फिर जोर पकड़ गई है। इनमें जादवपुर विश्वविद्यालय भी शामिल है। इससे पहले दिन में आयोजित एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। उन्होंने राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि छात्र संघ के चुनाव होंगे या नहीं।

सज्जन कुमार के घर ...

सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया- द्वारा सामूहिक हत्यारे सज्जन कुमार के घर जाकर उसकी मौत पर शोक व्यक्त करने की कड़ी निंदा करते हैं। यह तब हो रहा है जब भाजपा ने हमेशा इन दोषियों के खिलाफ न्याय की हमारी लड़ाई का समर्थन किया है और उसे जेल में रखने में हमारा साथ दिया है। सहानुभूति पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए होनी चाहिए - जिनमें से कई लोग आज भी उन दिनों के खौफ के साये में जी रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन तीनों सांसदों के बहिष्कार किया जाना चाहिए। तीनों सांसदों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने और सभी से जवाब तलब की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए एच एस फुलका ने कहा कि भाजपा का रुख शुरू से ही साफ रहा है। 42 सालों से पार्टी दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करती रही है और इस लड़ाई का पूरा समर्थन किया है।

कोकराझाड़ में बीवीसी और बीएमसी की संयुक्त बैठक संपन्न

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी मजबूत करने पर जोर

कोकराझाड़ (हिंस/विभास)। कोकराझाड़ के बोडोफा नगर स्थित बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार को बोड़ोलैंड विजिलेंस कमेटी (बीवीसी) और बोड़ोलैंड मॉनिटरिंग कमेटी (बीएमसी) की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में 40 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत बीटीसी परिषद एसेंबली के उपाध्यक्ष दिवंगत बिजित ग्वरा नार्जारी और बक्तार अली अहमद की स्मृति में एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी की ओर से पूर्व विधायक एवं एएलए की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य परमेश्वर ब्रह्म ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रणजीत कुमार वारी ने दोनों समितियों के उद्देश्य, भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग समितियों के कामकाज और जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि बोड़ोलैंड मॉनिटरिंग कमेटी (बीएमसी) एक सक्रिय पर्यवेक्षी तंत्र के रूप में कार्य करेगी। समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की लगातार निगरानी, उनके प्रदर्शन का आकलन और आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे। योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यकता के अनुसार नियमित और आकस्मिक ऑडिट करने के साथ-साथ व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव देगी। बैठक में पिछले पांच वर्षों के दौरान लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने पर भी चर्चा हुई। उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित अनियमितताओं की पहचान करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समग्र कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एसओपीडी 2026-27 के आवंटन एवं देनदारियों के भुगतान, एफआरबीएम एक्ट तथा डीएफपी रूल्स, 2022 के प्रावधानों और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं, बोड़ोलैंड विजिलेंस कमेटी (बीवीसी) विभिन्न विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करेगी। समिति विभागों एवं योजनाओं में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, अधिक जवाबदेही की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की समीक्षा करने तथा और समितियों को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की जांच एवं उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक के अंत में बीटीसी के विभिन्न विभागों के कामकाज तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का तामुलपुर जिला प्रशासन का आह्वान

तामुलपुर (हिंस)। तामुलपुर जिले में नशीले पदार्थों के अवैध इस्तेमाल, तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है। इस संबंध में शनिवार को जिला आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में जिला आयुक्त सिमी करण की अध्यक्षता में नार्कोटिक्स कंट्रोल से संबंधित जिला स्तरीय समिति की अगस्त माह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों, अवैध तस्करी पर रोक, शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान स्कूलों और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों की मौजूदगी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही, कुछ स्थानों पर पहले से संचालित शराब की दुकानों के समीप शैक्षणिक संस्थानों को स्थानांतरित किए जाने के मामलों पर भी चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तामुलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के आसपास गुटखा, सिगरेट आदि की बिक्री की शिकायतों पर भी बैठक में चर्चा हुई। जिला आयुक्त सिमी करण ने शिक्षण संस्थानों के आसपास ऐसे उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। बैठक में कुमारीकाटा, नाओकाटा और काउरबाहा सहित कुछ क्षेत्रों की फार्मेसियों में खाली सिरिंज की बिक्री के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। नशे के आदी लोगों द्वारा इनके संभावित दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि जिले के 30 गांवों में अभियान चलाकर भांग, पोपी आदि नशीले पौधों की खेती की जांच की गई, लेकिन अभियान के दौरान ऐसी खेती का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं, एसएसबी के सहयोग से वन विभाग द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। जिले के रास्ते नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बैठक में *आशा भवन* के पंजीकरण सहित अन्य संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई।

नगांव लोस उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पांच नेताओं ने मांगा टिकट

गुवाहाटी (हिंस)। असम की नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट के लिए पांच नेताओं ने आवेदन किया है। पार्टी सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। टिकट के दावेदारों में पूर्व विधायक शिवामणि बोरा और दुर्लभ सुमुआ के अलावा इमदाद हुसैन, मैदुल इस्लाम खान और रंजीत बर्मन शामिल हैं। पार्टी के टिकट के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। सभी दावेदारों ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पक्ष में एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य डिमांड ड्राफ्ट तथा मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति पार्टी कोषाध्यक्ष के समक्ष जमा की। नगांव लोकसभा सीट पूर्व सांसद प्रद्युत बरदलै के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। बरदलै ने अप्रैल में हुए असम विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में भाजपा का दामन थाम लिया था। निर्वाचन आयोग ने अभी तक नगांव लोकसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है।

तामुलपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

तामुलपुर (हिंस)। तामुलपुर जिला की जिला सड़क सुरक्षा समिति की अगस्त माह की बैठक आज जिला आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता तामुलपुर की जिला आयुक्त सिमी करण ने की। बैठक की शुरुआत में पिछले माह आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही पूर्व में लिए गए निर्णयों की प्रगति एवं उनके अनुपालन की समीक्षा की गई। इस दौरान जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, पार्किंग व्यवस्था तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विशेष रूप से द्वारकुची क्षेत्र में पार्किंग की समस्या पर चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में पुलिस विभाग की ओर से बताया गया कि पिछले माह तामुलपुर जिले में कुल 7 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। बगाजुली, डोंगपार, दरंगामेला, कुमारीकाटा सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुई इन दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत तथा 6 लोग घायल हुए। जिला आयुक्त सिमी करण ने संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण एवं चिन्हित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, वाहन चलाते समय सतर्कता तथा दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. दीपांकर नाथ, सहायक आयुक्त अनुपम डेका, निर्वाचन अधिकारी प्रांजलप्राण सैकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मल घोष, तामुलपुर राजस्व चक्र अधिकारी एलिमा कांडुलना सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जन्मदिन मनाने गए तीन युवकों की तालाब में डूबने से मौत

जोरहाट (हिंस)। असम के जोरहाट जिले के चिनामरा चाय बागान में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन युवकों-किशोरों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अक्षत कुमार रॉय, सुशांत पटेल और रेहान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, जोरहाट के फांसीआली इलाके से करीब 10-12 युवकों और किशोरों का दल जन्मदिन की पार्टी मनाने चिनामरा चाय बागान पहुंचा था। पार्टी के बाद कुछ युवकों के तालाब में उतरने की आशंका जताई जा रही है। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। काफी देर तक तलाश अभियान चलाने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तीनों के शव तालाब से बरामद किए। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न, दो गिरफ्तार

कोकराझाड़ (हिंस/विभास)। कोकराझाड़ में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खिरोद दास (48) और अजय राजबहा (35) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मामले में कोकराझाड़ थाना में बीएनएस की धारा 127(2), 75(2), 76 तथा पास्को एक्ट की धारा 8/12/17 के तहत केस संख्या 133/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अजय राजबहा, जो ई-रिक्शा चालक है, कथित तौर पर एक नाबालिग छात्रा को दूसरे रास्ते से ले जाकर आरएनबी रोड स्थित *ब्लू डायमंड* रेस्टोरेंट में ले गया। आरोप है कि उसने छात्रा का स्कूल बैग लेकर उसे ई-रिक्शा की सीट के नीचे बने बॉक्स में रखकर लॉक कर दिया। इसके बाद कथित तौर पर किशोरी को रेस्टोरेंट के अंदर एक केबिन में ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने किशोरी को शराब पिलाने की भी कोशिश की। गिरफ्तार आरोपियों में खिरोद दास *ब्लू डायमंड* रेस्टोरेंट का मालिक बताया गया है। स्थानीय स्तर पर रेस्टोरेंट में लंबे समय से कथित अनैतिक गतिविधियां संचालित होने के आरोप भी सामने आते रहे हैं।

नेपाल में जलप्रलय के बीच असम के 12 लोग लापता, सरकार लगातार नेपाल के संपर्क में

गुवाहाटी (हिंस)। नेपाल में आयी भीषण बाढ़ और जलप्रलय के बीच असम के 12 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। असम सरकार के अनुसार, लापता लोगों में कार्बी आंग्लांग, गोलाघाट, होजाई, गुवाहाटी और नलबाड़ी के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि अब तक असम के 12 लोगों के नेपाल में लापता होने की सूचना सरकार को मिली है। उन्होंने कहा कि यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार हर पल नेपाल सरकार के संपर्क में है और वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

काजीरंगा के संवेदनशील क्षेत्र में कटौती के विरोध में हाजो में कांग्रेस की पदयात्रा

कामरूप (हिंस)। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र को कम किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यव्यापी पदयात्रा के तहत शनिवार को हाजो-शुवालकुची ब्लॉक कांग्रेस ने भी विरोध मार्च निकाला। पदयात्रा हाजो के सातदला चौक से शुरू होकर हाजो राजस्व चक्र कार्यालय परिसर तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने *काजीरंगा बचाओ, पर्यावरण बचाओ* और *विकास चाहिए, लेकिन प्रकृति को नष्ट करके नहीं* जैसे नारे लगाते हुए प्रस्ताव के खिलाफ विरोध जताया।

मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम के साथ बीटीसी उपमुख्य कार्यकारी सदस्य रिहोन दैमारी की बैठक

कोकराझाड़ (हिंस)। बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के उपमुख्य कार्यकारी सदस्य एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी रिहोन दैमारी ने शनिवार को खानापारा स्थित बोड़ोलैंड गेस्ट हाउस में मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम के न्यासियों के साथ बैठक की। बैठक में गुवाहाटी के रूपनगर स्थित बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मेमोरियल जर्नलिस्ट्स गेस्ट हाउस की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम के पदाधिकारियों ने गेस्ट हाउस की वर्तमान स्थिति, संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित जानकारी रिहोन दैमारी के समक्ष रखी। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रकार गेस्ट हाउस का निर्माण तत्कालीन बोड़ोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल (बीएसी) तथा बीटीसी सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया था। वर्तमान में इसका प्रबंधन एवं संचालन मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम द्वारा किया जा रहा है। बैठक में गेस्ट हाउस के उचित संचालन, नियमित रखरखाव और दीर्घकालिक स्थायित्व के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा दैनिक प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों, मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकताओं, वित्तीय स्थायित्व तथा पत्रकारों के लिए इस सुविधा को निरंतर उपयोगी बनाए रखने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया। रिहोन दैमारी ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडिया पेशेवरों के लिए यह गेस्ट हाउस एक उपयोगी और गरिमापूर्ण सुविधा है। विशेष रूप से बीटीसी क्षेत्र से जुड़े पत्रकारों सहित गुवाहाटी आने वाले मीडिया कर्मियों के लिए यह सुविधा उनके पेशेवर एवं आधिकारिक कार्यों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने गेस्ट हाउस के नियमित रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए पारदर्शी और टिकाऊ व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही, नियमित रखरखाव एवं संचालन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय वित्तीय स्रोतों तथा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था तलाशने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में आवश्यकता के अनुसार गेस्ट हाउस में मरम्मत, नवीनीकरण और आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई, ताकि यहां आने वाले पत्रकारों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर वातावरण मिल सके। संबंधित सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम के न्यासियों ने गेस्ट हाउस के प्रबंधन एवं रखरखाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों से उपमुख्य कार्यकारी सदस्य को अवगत कराया और मौजूदा चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक सहयोग एवं समर्थन का आग्रह किया। रिहोन दैमारी ने आश्वासन दिया कि बैठक में उठाए गए मुद्दों की उचित रूप से समीक्षा की जाएगी और संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर आवश्यक कदम उठाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। बैठक में बीटीसी के आई एंड पीआर विभाग के ओएसडी प्रदीप ब्रह्म तथा गगन चंद्र नार्जारी उपस्थित रहे। वहीं मीडिया ट्रस्ट ऑफ असम की ओर से अध्यक्ष प्रशांत ज्योति बरुवा, सचिव रमणी बर्मन तथा न्यासी बेदब्रत देवा मिश्रा, निर्मल रे, कुंज मोहन राय और गरख्वदाओ बसुमतारी मौजूद रहे।

कामरूप जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

कामरूप, अमीनगांव (विभास)। कामरूप जिला स्वास्थ्य समिति की एक विस्तृत समीक्षा बैठक आज अमीनगांव स्थित एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। कामरूप के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य जिले की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समग्र स्थिति की समीक्षा करना और आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता को और अधिक मजबूत करना था। बैठक में जिला आयुक्त ने कामरूप जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, आम जनता के लिए सेवाओं की सुलभता और जमीनी स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। जिला आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने में आ रही विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं की जानकारी ली तथा इन चुनौतियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को समन्वित और समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए। जिला आयुक्त ने जिले के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और सेवाओं को मजबूत करने, आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाने के अलावा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य-उन्मुख कदम उठाने पर भी जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त जिला आयुक्त (स्वास्थ्य) मोनिका बोरगोहेन, कामरूप के संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अजीत दास सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

गुवाहाटी : राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित

खेल और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने पर जोर

गुवाहाटी (हिंस)। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर शनिवार को सरुसजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुवा खेल परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेल, फिटनेस तथा असम की समृद्ध पारंपरिक खेल संस्कृति को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में असम के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बिस्वजीत दैमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित किया गया और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की गई। अपने संबोधन में मंत्री दैमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस असम में मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और बच्चों एवं युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। उन्होंने राज्य में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें निखारने के लिए आयोजित खेल महारण असम की सफलता का उल्लेख किया और कहा कि ऐसी पहलों पर आगे भी जोर दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद के भारतीय खेलों में उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए मंत्री ने कहा कि उनका जीवन और उपलब्धियां आज भी खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अनुशासन, समर्पण और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। समारोह के दौरान रस्साकशी, बतख पकड़ने, मुर्गों की लड़ाई, भारतीय तीरंदाजी, टेकेली भोंगा और धीमी साइकिल दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा खुम्भलैनाई (बोड़ो कुश्ती), नाव खेलोर गीत, महाओ, थांग-ता, रिमिन नालेबाओ और पेंग वॉक जैसी पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया गया।

गौहाटी विश्वविद्यालय की पहल : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 5,000 शैक्षणिक सामग्री का वितरण

गुवाहाटी (हिंस)। हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित शिवसागर जिले के छात्रों की शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से, गौहाटी विश्वविद्यालय ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कुलपति प्रोफेसर ननी गोपाल महंत के नेतृत्व में और विश्वविद्यालय प्रेस के सहयोग से 5,000 शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। गौहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपेन बेजबरुवा और प्रोफेसर विकास गोगोई ने अन्य सहयोगियों के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद स्कूलों का दौरा किया, छात्रों के साथ बातचीत की और 15 स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच 3,500 से अधिक शैक्षणिक किट वितरित किए। इसके अलावा, 1,500 अन्य किट जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को सौंपे गए। इस पहल के बारे में बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर ननी गोपाल महंत ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदाओं से छात्रों की शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसे कठिन समय में उनके साथ खड़े होना एक विश्वविद्यालय के रूप में हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। शैक्षणिक किट वितरण की इस पहल के माध्यम से हम केवल अध्ययन सामग्री प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए अपने समर्थन का संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गौहाटी विश्वविद्यालय जरूरत के समय हमेशा समाज के साथ खड़ा रहने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज का कल्याण विश्वविद्यालय का हमेशा मुख्य दायित्व रहा है। गौहाटी विश्वविद्यालय प्रेस के निदेशक प्रोफेसर अंकुरण दत्त ने प्रेस के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ प्रोफेसर दीपेन बेजबरुवा और प्रोफेसर विकास गोगोई को इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया है।

धुबड़ी : भीषण गर्मी को ले स्कूलों के समय में बदलाव किए गए

धुबड़ी (विभास)। धुबड़ी के जिला आयुक्त के निर्देश के अनुसार और जन कल्याण हित में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय की सामान्य समय में बदलाव किया गया है। नए समय धुबड़ी जिला के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर 31 अगस्त यानी सोमवार से लागू होंगे। स्कूलों का संशोधित समय इस प्रकार है एलपी स्कूल (लोअर प्रायमरी) सुबह 7-30 से 11-30 बजे तक। एमई स्कूल सुबह 7-30 से दोपहर 12 तक। वहीं हाई और हायर सेकेंडरी सुबह 7-30 से दोपहर 12-30 तक चलेगी। सुबह की प्रार्थना सभा भीषण गर्मी से बचने के लिए स्कूलों के बरामदे किए जाने की निर्देश दिया गया है।

संपादकीय

'प्रलय' के 189 ग्लेशियर

भारत भी प्रलय और तबाही के कगार पर है। नेपाल में भी महाविनाश अब भी दस्तक दे रहा है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अध्ययन किए हैं और उनकी रपटों के निष्कर्ष हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में करीब 7500 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। उनमें से 189 झीलें 'रेड जोन' में हैं, क्योंकि ये कभी भी टूट-फूट कर 'प्रलय' मचा सकती हैं। तब तबाही निश्चित है। एक रपट यह भी है कि 491 सालों में 254 बार ग्लेशियर झीलें फट चुकी हैं। फिलहाल उत्तराखंड में 'हैंगिंग ग्लेशियर' सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अध्ययन में यह सामने आया है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर हजारों छोटी-बड़ी झीलें हैं। सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में ही 3219 ग्लेशियर झीलों की पहचान की जा चुकी है। कुल 2431 ग्लेशियर झीलें 10 हेक्टेयर से भी बड़ी हैं। घोर चिंता यह है कि एनडीएमए ने इन 189 झीलों को 'अत्यधिक जोखिम' की श्रेणी में रखा है। सवाल यह है कि क्या हमारे भू-वैज्ञानिक, विशेषज्ञ इन झीलों के 'प्रलय' से देश के संभावित हिस्सों को बचाने में सफल नहीं हो सकते? क्या अब पर्यावरण, जलवायु-परिवर्तन और वैश्विक गर्मी के असंतुलन बदला लेने की स्थिति में आ गए हैं? नेपाल के संदर्भ में भी चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी की है कि आगामी 3 दिन (शुक्रवार समेत) खतरे से भरे हैं। ग्लेशियर झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ, तो झील में दरार पडने का खतरा है, नतीजतन वह 'प्रलयी सैलाब' में तबदील हो सकता है। यानी नेपाल में खतरे और विनाश की घंटियां अब भी बज रही हैं। नेपाल छोटा-सा देश है, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था 4.48 लाख करोड़ रुपए है। मौजूदा जल-प्रलय ने नेपाल की करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां तबाह कर दी हैं। सरकार ने फिलहाल यह आकलन किया है। शुक्रवार सुबह तक 469 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है, क्योंकि इतने शव बरामद कर लिए गए हैं। मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश-विदेश के करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 288 भारतीयों के सुराग अभी तक नहीं मिले हैं। इस त्रासद घड़ी में विश्व बैंक ने 25 अरब रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। कुछ और देशों ने भी आर्थिक ऐलान किए हैं। भारत की सेना, एनडीआरएफ, एसएसबी आदि के जवान और डॉक्टर-नर्सिंग स्टाफ नेपाल को संकट से उबारने में संलग्न हैं। भारत लगातार राहत-सामग्रियों की भी आपूर्ति कर रहा है। बहरहाल हमारे सामने ग्लेशियर झीलों के अलावा, अल-नीनो, ग्लेशियर के निरंतर पिघलने, शहरी प्रदूषण और बीमारियां, कृषि-संकट आदि भी आसन्न तबाही और त्रासदियों की दस्तक दे रहे हैं। भारत कई जल-प्रलय झेल चुका है। जून, 2013 में केदारनाथ के 'प्रलय' और अलकनंदा-मंदाकिनी नदियों की बाढ़ में हजारों मौतें हो गई थीं। उसे 'सबसे बड़ी त्रासदी' करार दिया गया था। चमोली-ऋषि गंगा घाटी में ग्लेशियर फटा था, जिसमें 200 मौतें हुई थीं। केरलम के वायनाड में भूस्खलन और मूसलाधार बारिश में न केवल 400 के करीब मौतें हुईं, बल्कि कई गांव भी तबाह हो गए। नामोनिशान भी नहीं बचा। भारत में चक्रवात, भूकंप, सैलाब आते रहे हैं, बादल भी फटते हैं, बिजली भी गिरती है, नतीजतन असंख्य मौतें होती रही हैं। हालांकि अब समय-पूर्व कुछ जानकारियां दी जाती हैं, चेतावनी भी जारी की जाती है, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक भेजा जाता है, लिहाजा त्रासदियां कम हुई हैं, लेकिन खतरे आज भी बरकरार हैं। सवाल है कि आज हम कितना तैयार हैं? कितने सतर्क हैं? कितने संसाधन और नए शोध हैं, जो हमारी रक्षा कर सकते हैं? गौरतलब तो यह है कि एनडीएमए ने उत्तराखंड में ही चिह्नित 426 बड़ी ग्लेशियर झीलों में से 25 को 'संवेदनशील' और 13 झीलों को 'अति संवेदनशील' आंका है। इनमें भिलंगना घाटी में मौजूद 'मसर ताल' बेहद संवेदनशील बताई गई है। विनाश और त्रासदियों के लिए एक ही झील पर्याप्त है, लिहाजा हमें अभी से सतर्क होना चाहिए कि नदियों के किनारे निर्माण नहीं हों। मंदिर भी नदी किनारे न हों और सरकार को बाध्य किया जाए कि नदियों को आपस में जोडने का काम अब युद्धस्तर पर किया जाए।

नेपाल में भी महाविनाश अब भी दस्तक दे रहा है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अध्ययन किए हैं और उनकी रपटों के निष्कर्ष हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में करीब 7500 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। उनमें से 189 झीलें 'रेड जोन' में हैं, क्योंकि ये कभी भी टूट-फूट कर 'प्रलय' मचा सकती हैं। तब तबाही निश्चित है। एक रपट यह भी है कि 491 सालों में 254 बार ग्लेशियर झीलें फट चुकी हैं। फिलहाल उत्तराखंड में 'हैंगिंग ग्लेशियर' सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अध्ययन में यह सामने आया है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर हजारों छोटी-बड़ी झीलें हैं। सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में ही 3219 ग्लेशियर झीलों की पहचान की जा चुकी है। कुल 2431 ग्लेशियर झीलें 10 हेक्टेयर से भी बड़ी हैं। घोर चिंता यह है कि एनडीएमए ने इन 189 झीलों को 'अत्यधिक जोखिम' की श्रेणी में रखा है। सवाल यह है कि क्या हमारे भू-वैज्ञानिक, विशेषज्ञ इन झीलों के 'प्रलय' से देश के संभावित हिस्सों को बचाने में सफल नहीं हो सकते? क्या अब पर्यावरण, जलवायु-परिवर्तन और वैश्विक गर्मी के असंतुलन बदला लेने की स्थिति में आ गए हैं? नेपाल के संदर्भ में भी चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी की है कि आगामी 3 दिन (शुक्रवार समेत) खतरे से भरे हैं। ग्लेशियर झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ, तो झील में दरार पडने का खतरा है, नतीजतन वह 'प्रलयी सैलाब' में तबदील हो सकता है। यानी नेपाल में खतरे और विनाश की घंटियां अब भी बज रही हैं। नेपाल छोटा-सा देश है, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था 4.48 लाख करोड़ रुपए है। मौजूदा जल-प्रलय ने नेपाल की करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां तबाह कर दी हैं।

सीमा व्यापार, कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीमा-पार सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ

डोभाल की कूटनीति और भारत-चीन संबंधों की नई करवट

भारत और चीन के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों की तल्खी के बाद अब संवाद, संयम और व्यावहारिक सहयोग का एक नया दौर दिखाई दे रहा है। इसे किसी अचानक आए परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों को साथ लेकर चलने वाली एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इस बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है। 25 अगस्त को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने इस प्रक्रिया को ठोस आधार दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा निर्धारण की दिशा में शीघ्र एवं सार्थक प्रगति करने तथा सैन्य-द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। डोभाल की बीजिंग यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल सीमा विवाद पर बातचीत नहीं थी। यह उस व्यापक प्रश्न पर विमर्श था कि क्या भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के बावजूद सह-अस्तित्व, स्थिरता और पारस्परिक हितों का रास्ता तलाश सकते हैं। दोनों देशों ने दो अतिरिक्त सैन्य संपर्क-बिंदु और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में दो अतिरिक्त सैन्य दूरभाष संपर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है। सीमा व्यापार, कैलाश-मानसरोवर यात्रा और सीमा-पार सहयोग को भी आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सुरक्षा और कूटनीति को परस्पर विरोधी नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है-मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था ही प्रभावी कूटनीति की आधारभूमि बन सकती है। चीन के संदर्भ में भी भारत का संदेश यही रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना द्विपक्षीय संबंधों का पूर्ण सामान्यीकरण संभव नहीं है। 25वें दौर की वार्ता में यही भारतीय दृष्टिकोण प्रमुखता से सामने आया। डोभाल का व्यक्तित्व केवल वार्ताकार का नहीं, बल्कि सुरक्षा रणनीतिकार का है। वे लंबे समय तक खुफिया तंत्र में रहे, विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में काम किया और बाद में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख बने। भारत सरकार के अनुसार, उन्होंने पूर्वोत्तर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनकी कार्यशैली में एक उल्लेखनीय संतुलन दिखाई देता है-जहां आवश्यक हो वहां कठोरता और जहां अवसर हो वहां संवाद। उड़ी के बाद की सर्जिकल कार्रवाई, बालाकोट की कार्रवाई, डोकलाम संकट के दौरान कूटनीतिक प्रयास और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका इसी व्यापक दृष्टिकोण के उदाहरण माने जाते हैं। 2026 में उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया। भारत-चीन संबंधों का सबसे कठिन दौर वर्ष 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद आया। चार वर्षों तक सीमा पर सैन्य तनाव बना रहा। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच सैनिकों की पूर्ण वापसी और संबंधित विवादों के समाधान के बाद संबंधों को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसी वर्ष कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति तथा मतभेदों को संबंधों की समग्र दिशा को प्रभावित न करने देने पर जोर दिया था। यही वह बिंदु था जहां डोभाल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। दिसंबर 2024 में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत से शुरू हुई प्रक्रिया अब 25वें दौर तक पहुंची है। इस बार आठ बिंदुओं पर बनी सहमति संकेत देती है कि बातचीत केवल औपचारिकता नहीं रह गई है। सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ तथा कार्य समूहों को सक्रिय करना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलतफहमी रोकने के लिए मौजूदा सैन्य एवं कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग और नए संपर्क तंत्र बनाना व्यावहारिक विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत-चीन संबंध केवल सैनिक चौकियों और राजनयिक बैठकों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संपर्क भी रहा है। कैलाश-मानसरोवर यात्रा की पुनर्बहाली और विस्तार, सीमा व्यापार मार्गों को फिर खोलना तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। 2026 में कैलाश-मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथू ला, दोनों मार्गों से संचालित हुई है। 25वें दौर की वार्ता में तीन निर्धारित सीमा व्यापार केंद्रों को फिर खोलने की प्रगति का स्वागत किया गया तथा व्यापार और तीर्थयात्रा को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह छोटा कदम नहीं है। सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाना एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के लिए व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाना दीर्घकालिक शांति की सामाजिक नींव तैयार करता है। शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा एक अवसर भी है, परीक्षा भी है। इसी पृष्ठभूमि में 12-13 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावना जताई जा रही है। यदि यह यात्रा होती है तो यह सात वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उनके साथ लगभग चार सौ अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ सकता है। हालांकि 27 अगस्त तक चीन की ओर से उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए शी की संभावित यात्रा को केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी नहीं माना जाना चाहिए। यह भारत-चीन संबंधों की वास्तविक दिशा को परखने का अवसर हो सकती है। वर्ष 2019 का चेन्नई संवाद अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ था, लेकिन उसके एक वर्ष बाद गलवान ने संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया। अब यदि शी नई दिल्ली आते हैं तो दोनों देशों के पास उस टूटे हुए विश्वास को सावधानी से जोड़ने का अवसर होगा। लेकिन भारत को उत्साह में अपनी मूल सुरक्षा चिंताओं को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे, सीमा निर्धारण का लंबित प्रश्न और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पारदर्शिता जैसी चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए, भारत की नीति मित्रता की आकांक्षा, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। डोभाल की विशेषता यही है कि वे संवाद को कमजोरी नहीं बनने देते और शक्ति को टकराव का पर्याय भी नहीं बनाते। उनकी कूटनीति में संदेश स्पष्ट है-भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा कीमत पर नहीं, सहयोग चाहता है, लेकिन समानता के आधार पर। संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सीमा की वास्तविकताओं को भुलाकर नहीं। आज भारत-चीन संबंध जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां डोभाल की भूमिका संकटमोचक से आगे बढ़कर विश्वास-निर्माता और सुरक्षा-आधारित कूटनीति के सूत्रधार की बनती दिखाई देती है। 25वें दौर की वार्ता में हुई आठ सूत्रीय सहमति इसका प्रमाण है कि कठिनतम मतभेदों के बीच भी संवाद के रास्ते खुले रखे जा सकते हैं।

5 अगस्त को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता ने इस प्रक्रिया को ठोस आधार दिया है। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, सीमा निर्धारण की दिशा में शीघ्र एवं सार्थक प्रगति करने तथा सैन्य-द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने पर सहमति बनाई है। डोभाल की बीजिंग यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह केवल सीमा विवाद पर बातचीत नहीं थी। यह उस व्यापक प्रश्न पर विमर्श था कि क्या भारत और चीन प्रतिस्पर्धा के बावजूद सह-अस्तित्व, स्थिरता और पारस्परिक हितों का रास्ता तलाश सकते हैं। दोनों देशों ने दो अतिरिक्त सैन्य संपर्क-बिंदु और पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में दो अतिरिक्त सैन्य दूरभाष संपर्क स्थापित करने पर सहमति जताई है।

देश | दुनीया से

हिमालय के स्वभाव-सीमाओं को सम्मान से ही सुरक्षा

हिमालय केवल बर्फ, पत्थरों और ऊंची चोटियों की पर्वत-शृंखला नहीं है। वह दक्षिण एशिया की जल-सुरक्षा, मानसूनी व्यवस्था, जैव-विविधता, कृषि और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। लेकिन जिस हिमालय को हम स्थिर-अडिग मानते आए हैं, वह भू-गर्भीय दृष्टि से दुनिया की सबसे युवा और सक्रिय पर्वत-शृंखलाओं में है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप ने उसकी स्वाभाविक संवेदनशीलता को गंभीर बना दिया है। अब हिमालयी आपदाएं केवल अतिवृष्टि, बादल फटने या भूकंप तक सीमित नहीं हैं। बर्फ, चट्टान, हिमनद झील, नदी, मलबा और मानव निर्मित ढांचे मिलकर ऐसी बहु-आपदा शृंखलाएं पैदा कर रहे हैं, जिनका पूर्वानुमान कठिन और विनाश कई गुना हो सकता है। 26 अगस्त, 2026 को नेपाल के रसुवा ज़िले और तिब्बत-नेपाल सीमा के निकट भोटेकोशी-त्रिशूली नदी क्षेत्र की आपदा इसका नवीनतम उदाहरण है। वैज्ञानिक आकलन के अनुसार लगभग 5,200 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद का बड़ा हिस्सा टूटकर करीब 1,200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। बर्फ-चट्टानों के विशाल मलबे ने नदी को अस्थायी रूप से रोका। पानी जमा हुआ और अवरोध टूटते ही जल, मलबे और शिलाखंडों की प्रचंड धारा दौड़ पड़ी। आधे घंटे में नदी का जलस्तर नौ मीटर तक बढ़ गया। जलविद्युत परियोजनाएं, सड़कें, पुल व बस्तियां चपेट में आईं। सबसे चिंताजनक संदेश यह है कि विनाशकारी बाढ़ के लिए निचली घाटियों में भारी वर्षा होना आवश्यक नहीं है। हजारों मीटर ऊपर हिमनद या चट्टान टूट सकती है, नदी अवरुद्ध हो सकती है और प्राकृतिक बांध टूटने पर तुरंत नीचे विनाशकारी बाढ़ पहुंच सकती है। पिछले तीन दशकों की घटनाएं इसी खतरे का संकेत करती हैं। वर्ष 1998 में उत्तराखंड के मालपा में विशाल भूस्खलन ने पूरी बस्ती को नष्ट कर दिया। वर्ष 2000 में तिब्बती क्षेत्र से सतलुज में आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई। 2005 में पारिचू नदी पर बने प्राकृतिक अवरोध के टूटने से सतलुज घाटी फिर प्रभावित हुई। जून, 2013 की केदारनाथ त्रासदी में असाधारण वर्षा, हिम-पिघलाव, चोराबारी ताल से अचानक निकले पानी और विशाल मलबे ने मंदाकिनी घाटी में भयावह विनाश किया। फरवरी, 2021 की चमोली आपदा ने हिमालयी संकट का एक नया रूप सामने रखा। पता चला कि रोंटी क्षेत्र से विशाल चट्टान-हिमस्खलन हुआ था। करीब ढाई करोड़ घन मीटर चट्टान और बर्फ विनाशकारी मलबा-प्रवाह में बदल गई। ऋषिगंगा-तपोवन जलविद्युत परियोजनाएं चपेट में आईं व 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अक्तूबर, 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक हिमनद झील फटने से तीस्ता में आई बाढ़ ने दिखाया कि ऊंचे हिमालय में उत्पन्न संकट नीचे बांधों-पुलों, शहरों व सामरिक ढांचों को प्रभावित कर सकता है। दरअसल, इन घटनाओं का कारण कहीं अतिवृष्टि, कहीं हिमनद झील, कहीं चट्टान-हिम स्खलन और प्राकृतिक बांध का टूटना है। एक प्राकृतिक संकट दूसरे संकट को जन्म देता है। यही हिमालय की नई बहु-आपदा चुनौती है। दरअसल, भू-गर्भीय संरचना के चलते भारतीय भू-पट्टिका आज भी यूरेशियाई भू-पट्टिका की ओर बढ़ रही है। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोनों के बीच सापेक्ष टकराव करीब 40-50 मिलीमीटर प्रतिवर्ष है। इसी दबाव से हिमालय जन्मा, यही उसे अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र भी बनाता है। हिमालय में तीखी ढलानें, दरारों वाली चट्टानें, पुराने भूस्खलन क्षेत्र और तीव्र कटाव स्वाभाविक हैं। अतः यहां निर्माण व आबादी बढ़ाने से पहले कहीं अधिक सावधानी आवश्यक है। दरअसल, जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से हिमनद सिकुड़ रहे हैं। फलतः नई झीलें बनी और पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। इसरो ने 1984 से 2023 के उपग्रह चित्रों के आधार पर भारतीय हिमालयी नदी क्षेत्रों में दस हेक्टेयर से बड़ी 2,431 हिमनद झीलों का अध्ययन किया। इनमें 676 झीलों का में विस्तार पाया गया। हिंदुकुश-हिमालय क्षेत्र में लगभग 200 हिमनद झीलों को खतरनाक माना गया है। दरअसल, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा पहाड़ी ढलानों को अस्थिर कर सकती है। नदी में पानी के साथ भारी मलबा पहुंचा सकती है। हर हिमालयी आपदा को सड़क, सुरंग या बांध का परिणाम मानना गलत होगा। लेकिन अनियोजित निर्माण प्राकृतिक खतरे को बड़ी मानवीय त्रासदी में बदल सकता है। सड़कों के लिए पहाड़ काटना, ढलानों पर भारी निर्माण, नदी किनारे होटल और मकान, खराब जल-निकासी, निर्माण का मलबा नदियों में डालना तथा वन क्षेत्र का क्षरण जोखिम बढ़ाते हैं। जोशीमठ इसका उदाहरण है। दरअसल, शहर पुराने भूस्खलन के मलबे के मोटे जमाव पर स्थित है और वहां भू-धंसाव का खतरा ज्ञात था। 1976 की मिश्रा समिति ने भी भूमि की भार-वहन क्षमता की जांच के बिना भारी निर्माण न करने की सलाह दी थी। जलविद्युत ऊर्जा-सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अतः हर बांध को आपदा का कारण मान लेना उचित नहीं। लेकिन हिमनद झील, हिमस्खलन या भूस्खलन वाले क्षेत्र के नीचे बनी परियोजना की सुरक्षा सामान्य नदी परियोजना जैसी नहीं हो सकती। भारत सरकार ने 47 बांधों—38 चालू और नौ निर्माणाधीन—को हिमनद झील फटने से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले बांधों में चिन्हित किया है। पहाड़ी राज्यों हेतु जोखिम कम करने की योजना भी बनाई है।

आप का | नजरीया

पर्यटन की अधूरी तलाश

पर्यटकों की आमद का एक नक्शा विधानसभा सत्र में उभरा है। पिछले तीन साल में हिमाचल में 7.59 पर्यटक आए जबकि इस दौरान 262824 विदेशी सैलानी भी यहां आए। आंकड़ों की दृष्टि से आबादी से दोगुना पर्यटक आकर्षित करके हिमाचल अपनी संभावनाओं और क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 'क्वालिटी टूरिज्म' के नजरिये से अभी व्याख्या होनी बाकी है। हिमाचल की खूबी यह है कि यहां पर्यटन आगमन के कई कारण हैं, फिर भी हम मार्केटिंग में पीछे हैं। कुछ ऐसे सर्किट हैं जिन्हें हिमाचल ने अहमियत ही नहीं दी। सभी मौसम और सभी कारणों के पर्यटन का संतुलन बहुत जरूरी है ताकि हम हाई एंड टूरिज्म को आमंत्रित कर सकें। बेशक पिछले तीन सालों में दो लाख 65 हजार के करीब विदेशी पर्यटक हिमाचल आए, लेकिन इनके द्वारा खर्च की गई राशि अति उत्तम नहीं। प्रायः बजट टूरिस्ट ही हिमाचल आ रहे हैं। कसोल और धर्मकोट में आ रहे विदेशी पर्यटक कई बार भारतीय सैलानियों से भी कम खर्चीले होते हैं। दूसरी ओर पर्यटकों की बढ़ती तादाद में मंदिरों के दर्शन की रूटीन ही नजर आती है। तीसरे सप्ताहांत पर्यटन की मंजिलें केवल कुछ स्थलों पर ही रहती हैं। चौथे युवा पर्यटकों का आगमन सीमित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में पूरे हिमाचल का प्रतिनिधत्व नहीं करता है। ऐसे में हिमाचल में पर्यटन की तलाश अधूरी है। यह आंकड़ों की जुबान से भले ही अच्छी लगे, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर हिमाचल के संदर्भ अभी खाली हैं। हिमाचल की खोज जिस दिन हाई एंड टूरिस्ट करेगा, उस दिन पर्यटन की आर्थिक भागीदारी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर सप्ताहांत पर्यटन के साथ-साथ पूरे हफ्ते या इससे ज्यादा विश्राम का पर्यटन फैले, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हिमाचल में हाई एंड पर्यटन की जरूरतें अभी समझी ही नहीं गईं। ट्राइबल, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन को महत्त्व मिले, तो विविध आकर्षणों की तरफ विदेशी दौड़े आएंगे। शिमला के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व को देखते हुए सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, जबकि धर्मशाला, डलहौजी, मकलोडगंज, मनाली व कसौली में विदेशी बजट टूरिस्ट ही आ रहे हैं। हिमाचल में अधिक स्टे के लिहाज से युवा पर्यटक या यूं कहें कि कारपोरेट जगत से जुड़े युवा आ रहे हैं। इनकी जरूरतें हालांकि सीमित हैं, फिर भी इस श्रेणी के पर्यटक ज्यादा दिनों के लिए बार-बार हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल में देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए साहसिक व खेल पर्यटन भी सौगात बन रहा है। अकेले धर्मशाला में ही आईपीएल तथा अन्य क्रिकेट मैचों के जरिए हर साल दो लाख के करीब देशी-विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हाई एंड पर्यटक की तलाश में हिमाचली अधोसंरचना में तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन महापर्यटन की दृष्टि से कई प्रयास करने होंगे। महामहिम दलाई लामा की उपस्थिति से लाभ उठाते अगर काल चक्र आयोजन के लिए स्थायी सुविधाएं कहीं धर्मशाला-मनाली के बीच विकसित की जाएं, तो यह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की नई मंजिल हो सकता है। पौंग तथा अन्य कृत्रिम झीलों में साहसिक खेलों तथा अन्य सुविधाओं का विस्तार हो, तो यह पर्यटन के वार्षिक मेलों का प्रसार करेगा। मंदिरों की आय से धार्मिक पर्यटन की रूपरेखा में गुणवत्ता, धार्मिक-सांस्कृतिक एहसास में बढ़ोतरी की जाए, तो हाई एंड पर्यटन बढ़ेगा। हिमाचल में फोरलेन मार्गों के विकास के साथ हाई एंड पर्यटन को महत्त्व मिले, तो कई नए डेस्टिनेशन उभर सकते हैं। हिमाचल में पर्यटन विकास को होटलों से अलग मनोरंजन पार्कों, साइंस सिटी, प्राकृतिक नजारों और जल संसाधनों के इर्द-गिर्द समृद्ध करना होगा। जिस दिन हिमाचल अपने सीमांत क्षेत्रों को भी पर्यटन आकर्षणों में सम्मिलित कर पाया, उस दिन से हाई एंड पर्यटन का श्रीगणेश हर स्थान पर हो जाएगा।

पिछले तीन साल में हिमाचल में 7.59 पर्यटक आए जबकि इस दौरान 262824 विदेशी सैलानी भी यहां आए। आंकड़ों की दृष्टि से आबादी से दोगुना पर्यटक आकर्षित करके हिमाचल अपनी संभावनाओं और क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 'क्वालिटी टूरिज्म' के नजरिये से अभी व्याख्या होनी बाकी है। हिमाचल की खूबी यह है कि यहां पर्यटन आगमन के कई कारण हैं, फिर भी हम मार्केटिंग में पीछे हैं। कुछ ऐसे सर्किट हैं जिन्हें हिमाचल ने अहमियत ही नहीं दी। सभी मौसम और सभी कारणों के पर्यटन का संतुलन बहुत जरूरी है ताकि हम हाई एंड टूरिज्म को आमंत्रित कर सकें। बेशक पिछले तीन सालों में दो लाख 65 हजार के करीब विदेशी पर्यटक हिमाचल आए, लेकिन इनके द्वारा खर्च की गई राशि अति उत्तम नहीं। प्राय: बजट टूरिस्ट ही हिमाचल आ रहे हैं। कसोल और धर्मकोट में आ रहे विदेशी पर्यटक कई बार भारतीय सैलानियों से भी कम खर्चीले होते हैं। दूसरी ओर पर्यटकों की बढ़ती तादाद में मंदिरों के दर्शन की रूटीन ही नजर आती है। तीसरे सप्ताहांत पर्यटन की मंजिलें केवल कुछ स्थलों पर ही रहती हैं। चौथे युवा पर्यटकों का आगमन सीमित गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में पूरे हिमाचल का प्रतिनिधत्व नहीं करता है। ऐसे में हिमाचल में पर्यटन की तलाश अधूरी है। यह आंकड़ों की जुबान से भले ही अच्छी लगे, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर हिमाचल के संदर्भ अभी खाली हैं। हिमाचल की खोज जिस दिन हाई एंड टूरिस्ट करेगा, उस दिन पर्यटन की आर्थिक भागीदारी बढ़ जाएगी।

कुछ | अलग

मैं अभी अनशन पर हूं...

देखिए इन दिनों मैं बहुत बिजी हूं। मेरे पास सिर खुजलाने की फुर्सत नहीं है। कोरी गप्पें मारने की भी फुर्सत नहीं है। पत्नी से लडने की भी फुर्सत नहीं है। उसको शॉपिंग करवाने की फुर्सत भी नहीं है। अस्पताल की लाइन में लगने की फुर्सत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम करने की फुर्सत भी नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि जब मुझे फुर्सत ही नहीं है तो मैं आखिर कर क्या रहा हूं? आपका सवाल जायज है। मैं वही कर रहा हूं जो देशहित में जायज है। यानी मैं अनशन पर बैठा हूं। मीडिया मेरी वीडियो बना रहा है। कैमरामैन मेरी फोटो खींच रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं बराबर हाईलाइट हो रहा हूं। इसलिए दो दिन से मैंने कुछ खाया-पिया नहीं है। भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन मन मारकर बैठा हूं क्योंकि मैं अनशन पर बैठा हूं। अगर मैं अनशन से उठ जाऊंगा तो देश भटक जाएगा। लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मुझे कवरेज मिलना बंद हो जाएगी। युवा दिशा भ्रष्ट हो जाएगा।

दृष्टि | कोण

स्कूल सुधारने का अभियान और विकास

अब वह दौर आ गया है कि वोट देने के साथ ही देश की समस्याओं को लेकर सरकारों की नींद खोलनी के लिए आम लोगों को सडकों पर उतरना पड़ेगा। संख्या बल का इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। मुट्ठी भर लोग भी ताकतवर सरकारों से जनहित में अपनी बात मनवा सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उनके समर्थक जेन-जी के युवाओं ने देश भर में स्कूलों की दयनीय हालत का मुद्दा उठा कर यह साबित कर दिया कि चंद संघर्षशील नौजवान सरकारों का ध्यान आकर्षित करने और समस्या का समाधान कराने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। सीजेपी ने देश भर में स्कूलों की खराब हालत को सुधारने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की थी। इसी के तहत सीजेपी समर्थक जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के एक सरकारी स्कूल की हालत जानने के लिए पहुंचे। यह स्कूल भैंसों के बाड़े में टीन शेड के नीचे चल रहा था। हालांकि सीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्थानीय भाजपा विधायक के समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ हाथापाई की गई। उनकी गाडियों के शीशे फोड़ दिए गए। इसके बावजूद सीजेपी स्कूल की हालत मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देश को बताने में कामयाब हो गई। इस स्कूल को एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। इसका भवन बनाने की घोषणा की गई। चंद सीजेपी कार्यकर्ता तमाम दुश्वारियों के बावजूद स्कूलों के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए। जयपुर के स्कूल की हालत के बाद देश भर में सोशल मीडिया पर जर्जर स्कूलों की बाढ़ आ गई। राज्यों की सरकारें विकास की पोल खुलने से बैचेन हो गईं।

सोशल मीडिया पर स्कूलों की हालत को लेकर सरकारों की जम कर खिंचाई की गई। स्कूलों की हालत सामने आने के बाद राज्यों में विकास और तरक्की की असलियत उजागर हो गई। सरकारों को फजीहत के बाद स्कूलों की सुध लेने की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ गया। जयपुर के स्कूल की दुर्दशा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के बाद राजस्थान की भजन लाल सरकार ने स्कूलों की सुध ली। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में 3587 नई स्कूल बिल्डिंग और 83783 नए क्लासरूम बनाए जाने की घोषणा की। राजस्थान के 22589 विद्यालयों में व्यापक निर्माण कर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा। वहीं, स्कूलों में जरूरी सुविधाओं के विस्तार के लिए 13616 नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प के लिए करीब 12500 करोड़ रुपए के बजट से आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की योजना है। फिलहाल स्कूलों से जुड़े करीब 3006 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रक्रिया में हैं। सीजेपी के स्कूल सुधारो अभियान के बाद ही उत्तर प्रदेश में सरकार ने 3126 परिषदीय व उच्च प्राथमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण व मरम्मत 604 करोड़ रुपए से कराए जाने की घोषणा की। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए 302 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। इसमें खराब व जर्जर हो चुके भवनों की जगह नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पर 15.36 लाख रुपए खर्च होंगे। 2243 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत पर कुल 344.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी पहली किस्त के रूप में 172.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक 72 विद्यालयों में जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण, मरम्मत व अवस्थापना सुविधाओं के लिए विभाग की ओर से 9.62 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इसी तरह झारखंड और बिहार में पेपर लीक व धांधली के मामलों के बाद युवाओं के धरने-प्रदर्शन के बाद दोनों राज्यों की सरकारों को परीक्षाएं निरस्त करने पर विवश होना पड़ गया।

पंजाब सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को भेजे नोटिस, कर्मचारी पहुंचे राज्यपाल के दरबार

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाद अब और बढ़ता दिखाई दे रहा है। 27 अगस्त को हजारों कर्मचारी सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए। अब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों से पूछा जा रहा है कि कथित तौर पर अनधिकृत अवकाश लेने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए? सरकार की इस कार्रवाई के बीच सांझा मुलाजिम मंच ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को शिकायत दी है। संगठन ने आरोप लगाया कि 27 अगस्त को जालंधर के पीएपी ग्राउंड में कर्मचारियों और मुख्यमंत्री के बीच प्रस्तावित बैठक अंतिम समय पर नहीं हो सकी, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। कर्मचारियों ने इस अनुपस्थिति के लिए मुख्यमंत्री की एक दिन की सेलरी काटने की मांग की है। कर्मचारी संगठन के अनुसार बैठक 8 अगस्त को जारी आधिकारिक सूचना के तहत तय की गई थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जालंधर पहुंचे थे। संगठन का आरोप है कि मुख्यमंत्री के बैठक में नहीं आने की पहले से कोई स्पष्ट सूचना या ठोस कारण नहीं बताया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंच ने राज्यपाल को दिए प्रतिनिधित्व में यह भी आरोप लगाया कि बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मंच, प्रशासनिक तैयारियों और परिवहन सहित कई इंतजामों पर सरकारी धन खर्च हुआ, लेकिन बैठक नहीं होने के कारण यह खर्च बेकार गया। कर्मचारियों ने इसे प्रशासनिक लापरवाही और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, पंजाब के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते के लंबित बकाये, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने 27 अगस्त को सामूहिक आकस्मिक अवकाश का आह्वान किया था। संगठनों के अनुसार, बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद सरकार ने सभी विभागों से 27 अगस्त को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की सूची मांगी। अब ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे जा रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार की इस कार्रवाई को दबाव बनाने की कोशिश बताया है और कहा है कि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अब एक तरफ सरकार नोटिस के जरिए कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रविवार को होने वाली कर्मचारी संगठनों की बैठक में नोटिस, लंबित मांगों और सरकार के खिलाफ आगे के आंदोलन की रणनीति पर फैसला लिया जा सकता है।

अमृतसर में निहंग सिख की गोली मारकर हत्या

अमृतसर (हिंस)। बाबा बकाला साहिब में शुक्रवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस समय हुई, जब क्षेत्र में ऐतिहासिक रक्खड़ पुण्या मेले के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग मौजूद थे। मृतक की पहचान गांव मग्लानी निवासी राजा सिंह के रूप में हुई है। राजा सिंह निहंग वेशभूषा में था। उसका शव बाबा बकाला के सिविल अस्पताल के पीछे पड़ा मिला। उसके सीने और हाथ पर गोली लगने के निशान पाए गए। पुलिस को शव के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया। ब्यास थाने के एसएचओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को अस्पताल के पीछे निहंग वेशभूषा में एक युवक के शव की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं।

283 पंचायतों में खुलेगा *जीविका सुधा बिक्री केंद्र*, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का नया अवसर

सीवान (हिंस)। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जीविका दीदियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में सीवान में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीवान सदर प्रखंड की जीयाय पंचायत में जिले के प्रथम *जीविका सुधा बिक्री केंद्र* का शुभारंभ जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने फीता काटकर किया। इस पहल से जीविका दीदियों को व्यवसाय संचालन के साथ स्थानीय स्तर पर बाजार से जुड़ने और आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर आय के अवसरों से जोड़ना जरूरी है। *जीविका सुधा बिक्री केंद्र* ग्रामीण महिलाओं

को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आजीविका संवर्धन और उद्यमिता के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। जिले की सभी 283 पंचायतों को इस पहल से जोड़ने की योजना है। प्रथम चरण में 231 पंचायतों में *जीविका सुधा बिक्री केंद्र* खोले जाएंगे, जबकि शेष 52 पंचायतों को दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक जीविका दीदियों को स्थानीय स्तर पर व्यवसाय और आय के अवसर उपलब्ध होंगे। जीविका एवं सुधा (कॉम्फेड) के समन्वय से संचालित होने वाली इस पहल को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे जीविका दीदियों की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और वे अपने परिवार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दे सकेंगी।

हरियाणा में कचरे से पैदा होगी 50 मेगावाट बिजली, लगेंगे चार इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा में शहरी कचरा प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए राज्य सरकार ने चार इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में स्थापित होने वाले इन संयंत्रों में संचालन शुरू होने पर प्रतिदिन कुल 5 हजार टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे कुल 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इन संयंत्रों के अक्तूबर 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। शनिवार को नूंह में एमओयू होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये समझौते प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन संयंत्रों की स्थापना ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा की जाएगी, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी हरियाणा के शहरी विकास को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ प्रदेश में कचरा प्रबंधन के तौर-तरीकों में भी बड़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ कचरे के उचित प्रबंधन की चुनौती भी लगातार बढ़ रही है। कचरा केवल समस्या नहीं है, बल्कि सही तकनीक और वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से इसे ऊर्जा और उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट हिसार क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद और जींद जिलों के शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। इस प्लांट में प्रतिदिन 500 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और इससे न्यूनतम 5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन अपेक्षित है। दूसरा प्लांट अंबाला क्लस्टर में स्थापित किया जाएगा, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला जिलों के शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। यहां प्रतिदिन 900 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा और न्यूनतम 9 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन अपेक्षित है। तीसरा प्लांट फरीदाबाद क्लस्टर में स्थापित होगा, जिसमें फरीदाबाद जिला शामिल होगा।

मेवात कैडर के नव-नियुक्त 1054 प्राथमिक शिक्षकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के मेवात क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को नूंह की अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान मेवात कैडर के 1054 नव-नियुक्त प्राथमिक (पीआरटी) शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए शिक्षकों की तैनाती से क्षेत्र में शिक्षक-विद्यार्थी का अनुपात सुधरेगा और प्राथमिक शिक्षा का स्तर और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि वीर हसन खां मेवाती की शौर्य भूमि पर इतने बड़े आयोजन का होना मेवात क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर नव-नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा विषयक 22 स्टॉल की एक भव्य

प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। साथ ही, शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल को निखारने के लिए विशाल एलईडी स्क्रीन पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक प्रभावी प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित हुआ। इस दौरान *मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना* के तहत सम्मान राशि भी जारी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में नई भर्ती को युवाओं की योग्यता की जीत बताते हुए कहा कि पहले की सरकारों में भाई-भतीजावाद, जातपात, क्षेत्रवाद और पर्ची-खर्ची के हिसाब से नौकरी मिलती थी। बीजेपी की सरकार बनते ही बिना पर्ची-बिना खर्ची के 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर योग्य युवाओं का आत्मसम्मान लौटाया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में महज 86 हजार सरकारी नौकरियां दी थीं। उन्होंने पंजाब में भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया। इसी क्रम में बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले 70 प्रतिभाशाली बच्चों को *मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना* के तहत 39 लाख 90 हजार रुपए की सम्मान राशि जारी की गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 40 थी, जो इस बार बढ़कर 70 हो गई है। इसके अलावा *मुख्यमंत्री मेवात पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना* के तहत 1364 विद्यार्थियों को 52 लाख 44 हजार रुपए की छात्रवृत्ति भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिला के 450 स्कूल भवनों की डीपीआर तैयार हो चुकी है तथा सरकार ने 200 करोड रुपए जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों के सुधारीकरण पर 400 करोड रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि निपुण हरियाणा के तहत शिक्षकों के दो प्रशिक्षण चरण पूरे हो चुके हैं और अगले माह करीब 32 हजार पीआरटी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। इस दौरान शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने नव नियुक्त पीआरटी

संस्कृत के बिना आयुर्वेद का मूल स्वरूप अधूरा : प्रो. सतीश गंधर्व

चंडीगढ़ (हिंस)। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), पंचकूला में 11वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला में संस्कृत दिवस-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती का पूजन कर किया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों ने आयुर्वेद के मूल ग्रंथों की भाषा संस्कृत को सहेजने का संकल्प लिया। डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। संस्कृत के बिना आयुर्वेद का मूल स्वरूप अधूरा है। इसलिए संस्कृत में समाहित आयुर्वेद का ज्ञान-विज्ञान, संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के अनेक मूल एवं प्रामाणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचित हैं। ऐसे में आयुर्वेद के सिद्धांतों, चिकित्सा पद्धतियों और भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर गंधर्व ने कहा कि संस्कृत में केवल साहित्य, धर्म और अध्यात्म ही नहीं, बल्कि मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के माध्यम से सभी के सुख और कल्याण की कामना की गई है। इसके साथ ही, वसुधैव कुटुम्बकम पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने संस्कृत दिवस के माध्यम से विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान से जोडने के प्रयास का आह्वान किया। असिस्टेंट प्रोफेसर चंद्रमोहन द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त करते हुए बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद के मूल ग्रंथों एवं भारतीय ज्ञान परम्परा के आधारभूत माध्यम के रूप में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित किया गया तथा इसके अध्ययन, संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। इस अवसर पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मनीष पमनानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आकांक्षा राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनुराग कुशल, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धवल जी मकवाना, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अंकिता नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर महेश एम, चिकित्सा अधिकारी शीन्षा पी तथा बीएएमएस के विद्यार्थी मौजूद रहे।

सिख समुदाय ने फूंका सांसद दीपेंद्र हुड्डा का पुतला

सिरसा (हिंस)। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सिखों पर हुए अत्याचार के मामले में मुख्य आरोपी रहे पूर्व सांसद सज्जन कुमार को अपना आदर्श बताने पर सिख समाज ने शनिवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इससे पूर्व सिख समाज के लोग सिरसा के जनता भवन में एकत्रित हुए और वहां वक्ताओं ने वर्ष 1984 में कांग्रेस शासन के दौरान सिखों पर किए गए अत्याचारों की कड़ी आलोचना की। वक्ताओं ने कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा उस व्यक्ति को अपना आदर्श बता रहे हैं जिन्होंने सिखों के गले में टायर डालकर उन्हें मारने जैसा कठोर षड्यंत्र रचा जिसके लिए वे न्यायालय से भी दोषी ठहराए गए। उस दौर में महिलाओं से दुराचार करते हुए सिख कौम पर तीन दिन तक निरंतर अत्याचार करता रहा जबकि सिख पंथ ने सदैव देश की सुरक्षा और अध्यात्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। रोष जता रहे लोगों ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा सही मायने में सिखों की दुश्मन है। वर्ष 1984 में कांग्रेस ने देश में जातिगत तौर पर बांटने का षड्यंत्र रचा मगर देशवासियों ने इस एकता अखंडता को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में दरबार साहिब पर भी हमला हुआ जो निंदनीय घटना थी। वहां सिखों पर हमलों के दौरान अनेक निर्दोष लोग मारे गए। कांग्रेस ने उस दौरान नफरत की राजनीति की और अब ऐसे बयान पर सिख समुदाय कांग्रेस नेता की आलोचना करता है।

राजस्थान में सूखे जैसे हालात पर गहलोत ने सरकार को चेताया

बोले, समय रहते तैयारी जरूरी

जयपुर (हिंस)। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने और कई जिलों में बारिश की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सावन बीतने के साथ ही प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है और भादों में भी बारिश की उम्मीद क्षीण नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया कि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 17 जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। गहलोत ने कहा कि पाली, जालोर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर जैसे जिलों में सामान्य से 40 से 55 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि सूखे जैसी स्थिति का सबसे अधिक असर किसानों और श्रमिकों पर पड़ता है, इसलिए राज्य सरकार को अभी से आवश्यक तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल की इंदिरा रसोई और मनरेगा जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संकट के समय इन योजनाओं ने गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को सहारा दिया था। उन्होंने सरकार से खाद्यान्न का भंडारण बढ़ाने, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और शहरी रोजगार गारंटी योजना को मजबूत करने की मांग की।

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

कहा, महिलाओं को बुलाया 11 हजार देने, थमा दिए 1100 रुपए

लखनऊ (हिंस)। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रक्षाबंधन कार्यक्रम पर तीखा प्रहार किया है। राजभर ने अखिलेश पर *राखी घोटाला* करने का आरोप लगाया है। राजभर ने एक्स के जरिए कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर 11-11 हजार रुपए का प्रलोभन देकर महिलाओं को बुलाया गया लेकिन उन्हें महज 11 सौ रूपए का लिफाफा दिया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शनिवार जारी बयान में कहा है कि कहावत है कि लोगों का स्टेटस भले बदल जाए लेकिन आदत नहीं बदल सकती। आप (सपा) लोग सत्ता में रहें या न रहें, अपने खटकरमों से बाज नहीं आते। राजभर ने लिखा कि इस बार कुछ नहीं मिला तो *राखी घोटाला* करके बैठ गए? अरे कम से कम बहनों का मन और मान रख लिए होते।

वैसे कंसवादियों से रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर मर्यादित आचरण की उम्मीद करना बेवकूफी ही है। राजभर ने आगे लिखा कि दो दिन पहले अपने (सपा) दफ्तर में आप खूब धूम-धड़ाके के साथ लिफाफा वितरण समारोह किये, जिसमें 11-11 हजार रुपए का प्रलोभन दे के पहले तो महिलाओं को बुलाया, लेकिन पहुंची केवल बुर्कानशीं खवातीनें। अब मालूम चल रहा है कि उन खवातीनों को भी 10-10 हजार रुपए का चूना लगा दिए आप लोग। सबको 11 सौ रुपल्ली का लिफाफा थमा के चलता कर दिया गया? बाकी के रुपए कहां गायब कर दिए श्रीमान जी? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आपके (सपा) दफ्तर में चर्चा बहुत तेज है कि आपके ही विभीषणों ने हर पैकेट से करीब 10-10 हजार रुपए का राखी घोटाला किया है। वो सब भी सोचे होंगे कि *शाह-ए-बेखबर* को पता थोड़ी न चलेगा। ये तो भला हुआ कि कुछ खवातीनों ने लिफाफा चेक कर लिया और पाया कि इसमें तो केवल 11 सौ रुपल्ली रखा है। आपका परम हितैषी होने के नाते पहले भी सलाह दी है और फिर दे रहा हूं... *विभीषणों* से जितना जल्दी छुटकारा पा लेंगे उतना अच्छा होगा। ये सब आपकी लंका लगा के ही मानेंगे। जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराज सुहेलदेव।

अखिलेश ने भाजपा पर लगाया मतदाता सूची में गड़बड़ी कराने का आरोप

लखनऊ (हिंस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मतदाता सूची में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऐसे लोगों के नाम से भी फर्जी फॉर्म-7 भरवाकर वोट कटवाने का काम किया, जो दस्तखत तक करना नहीं जानते थे। अखिलेश यादव शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नंदलाल निषाद जो दस्तखत करना नहीं जानते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नकली दस्तखत कराकर वोट कटवाने का काम फर्जी फॉर्म-7 भरवाकर कराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि न कभी तानाशाही चली थी, न दानाशाही चलेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अखिलेश ने

कहा कि ये भाजापा की सरकार में स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भविष्य में अपने घोषणापत्र में ऐसा प्रावधान लाएगी, जिसके तहत गरीबों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सपा सरकार ठोस व्यवस्था करेगी। अखिलेश ने कहा कि जेपीएनआईसी समाजवादियों के लिए एक इमोशनल जगह है, जय प्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आवाहन किया था और उस समय देश में राजनैतिक बदलाव आया था। उस जगह को भी भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के मामले में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा का वादा तो किया, लेकिन बसें ही हटवा दीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जाट समाज में व्याप्त आक्रोश और मारे गए लोकप्रिय युवा गायक अंकित बालियान के दुखी पिता की बात सुनेंगे या उनसे भी उसी तरह पेश आएंगे, जैसा पहले एक दुखी मां के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वोटों की सगी है, जाट या किसी अन्य समाज की नहीं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आज जो जाट नेता अपने स्वार्थ के कारण भाजपा के साथ खड़े हैं, उनसे पूरा जाट समाज जवाब मांग रहा है। उन्होंने प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे और सड़कों के मामले में भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे चार हजार करोड़ से ज्यादा का बना है, मुख्यमंत्री ने तो अपनी सड़कों में भी गोलमाल कर लिया। बीजेपी के लोग प्रोग्रेसिव सोच के लोग नहीं हैं, इनका नकारात्मक नजरिया है। भाजपा ने हर चीज महंगी कर दी है। आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से है। समाजवादी सरकार बनेगी तो दाम बांधो के सिद्धांत पर काम करेंगे। इससे पहले सपा मुख्यालय में बड़े स्तर पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल कराया गया। इनमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा), कांग्रेस और इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) से आए कई नेताओं ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इनमें श्रावस्ती से एआईएमआईएम नेता अब्दुल मन्नान, पीलीभीत से पूर्व विधायक हेमराज वर्मा और प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक रामशिरोमणि शुक्ला प्रमुख रहे। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा मौर्य समेत कई पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। सपा सदस्यता कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि संकीर्ण सोच रखने वाले लोग पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंकख्यक)से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि न जाने क्यों ये पीडीए से घबराते हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी जितनी गंभीर है, उतनी गंभीरता किसी अन्य दल में नहीं दिखाई दे रही है।

नेपाल बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 100 तीर्थयात्रियों को बिहार सरकार ने किया रेस्क्यू, ट्रेन से हुए रवाना

पटना (हिंस)। नेपाल में आई बाढ़ के चलते काठमांडू में फंसे महाराष्ट्र के करीब 100 तीर्थयात्रियों को बिहार सरकार की मदद से सुरक्षित निकालकर उनके गृह राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर मानवीय पहल करते हुए बिहार सरकार ने राहत और सुरक्षित वापसी की पूरी व्यवस्था की। बिहार के मुख्यमंत्री के निर्देश और मुख्य सचिव तथा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव की निगरानी में सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने 28 अगस्त 2026 को त्वरित कार्रवाई की। सभी तीर्थयात्रियों को नेपाल सीमा से सुरक्षित एस्कॉर्ट कर सीतामढ़ी लाया गया। यहां उनके लिए भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। इसके बाद 29 अगस्त की रात करीब 2-30 बजे सभी तीर्थयात्रियों को सीतामढ़ी से पटना लाया गया। पटना जिला प्रशासन ने उन्हें ओपी साह सामुदायिक भवन में ठहराया। यहां भोजन, आवासन, चिकित्सा जांच और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के साथ समन्वय किया। इसके बाद पटना-पूर्णा एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त बोगियां जोड़ी गईं। 29 अगस्त को सुबह 7-30 बजे सभी तीर्थयात्रियों को विशेष व्यवस्था के तहत ट्रेन से महाराष्ट्र के लिए रवाना कर दिया गया। सुरक्षित और सम्मानजनक

वापसी के बाद तीर्थयात्रियों ने बिहार सरकार के साथ-साथ सीतामढ़ी और पटना जिला प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने बाढ़ के बीच की गई त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और समन्वित राहत प्रयासों के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

खाने-पीने की चीजों के पैकेट पर लाल चेतावनी अनिवार्य

चीनी, फैट और नमक की अधिक मात्रा वाले उत्पादों पर लाल रंग के षट्भुजाकार चिह्न से मिलेगी पहचान

नई दिल्ली

भारत में पैक किए गए खाद्य पदार्थों की खरीद अब और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह ऐसे खाद्य उत्पादों पर उच्च चीनी, उच्च वसा और उच्च नमक की चेतावनी लाल रंग में अनिवार्य करने जा रहा है, जिनमें इन तत्वों की मात्रा तय मानकों से अधिक होगी।

यह पहल उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर विकल्पों की पहचान करने और स्वस्थ निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से की जा रही है। एफएसएसएआई ने जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष दाखिल अपने छह पन्नों के हलफनामे में बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस चेतावनी को पैकेट या डिब्बे के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग के षट्भुजाकार (हेक्सागोनल) तस्वीर के रूप में अंकित किया जाएगा, ताकि ग्राहक इसे आसानी से पहचान सकें।

इसका फान्ट साइज पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन संबंधी जानकारी वाली तालिका में इस्तेमाल होने वाले फान्ट साइज से एक पाइंट बड़ा होगा। यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में गैर सरकारी संस्था 3एस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई फटकार के बाद दाखिल किया गया है। एफएसएसएआई ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित नियम दो चरणों में लागू किए जाएंगे, ताकि खाद्य उद्योग को अपने उत्पादों में आवश्यक बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पहले चरण में उन उत्पादों पर नियम लागू होंगे।

उदारीकरण के 35 सालः भारत आर्थिक महाशक्ति, फिर भी राज्यों में असमानता गहरी, देश की प्रति व्यक्ति आय में भारी वृद्धि के बावजूद, आय व विकास के अंतर ने बढ़ाई चुनौती

नई दिल्ली। भारत ने आर्थिक उदारीकरण के बाद पिछले तीन दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और प्रति व्यक्ति आय में भी 40 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है। लेकिन इस शानदार प्रगति के बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के बीच आय और विकास की खाई लगातार गहरी होती जा रही है, जो भविष्य के लक्ष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद भारत ने क्रय शक्ति समता के आधार पर दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस अवधि में भारत की प्रति व्यक्ति आय 40 गुना से अधिक बढ़ी है। हालांकि, विशाल आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी दुनिया के लगभग 140 देशों से पीछे है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक सुधारों का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच सका है, जिससे राज्यों के बीच आय और विकास का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् के अनुसार, आर्थिक गतिविधियां अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं जहां पहले से बुनियादी ढांचा और उद्योग मौजूद होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली और गोवा जैसे क्षेत्र लगातार प्रति व्यक्ति आय के शीर्ष पांच में बने हुए हैं, जबकि हाल ही में कर्नाटक भी इस सूची में शामिल हुआ है।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली में सीएनजी हुई 3.89 रुपये प्रति किलो महंगी, नई दरें लागू

नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के साथ अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नई दरें लागू हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने जारी एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमत 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोत्तरी की गई है। अब दिल्ली में इसकी नई कीमत 86.98 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले यह कीमत 83.09 रुपये प्रति किलो थी। वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का नया रेट 95.59 रुपये प्रति किलो हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ में सीएनजी का नया दाम 95.47 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। गुरुग्राम में अब यह 92.01 रुपये प्रति किलो पड़ रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में नया दाम 91.59 रुपये प्रति किलो हो गया है। आईजीएल ने जारी बयान में कहा कि सीएनजी के लिए जरूरी गैस का एक बड़ा हिस्सा आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से पूरा किया जा रहा है, जिसकी हाजिर या मौजूदा बाजार में कीमतें पश्चिम एशिया संकट में संघर्ष शुरू होने के बाद से बढ़ी हैं। उल्लेखनीय है कि, इस साल सीएनजी की कीमतों में यह पांचवीं बढ़ोतरी है।

पुणे स्थित वेयरहाउस का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द, भंडारण, पैकेजिंग और भ्रामक लेबलिंग में मिली गंभीर खामियां

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फारवर्डिंग (सीएंडएफ) इकाई का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई वाडकी, पुणे जिले के गोदाम में भंडारण, पैकेजिंग और वापस मंगाने की प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर की गई है। एफडीए ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने का आदेश 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है, जिसे कंपनी ने अदालत में चुनौती दी है। नियामक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में दवाएं सीधे फर्श पर रखी मिलीं और एक्सपायर्ड दवाओं के प्रबंधन में भी गंभीर कमियां पाई गईं। जून में हुए निरीक्षण में अधिकारियों ने डाक्टर के पर्चे पर बिकने वाली दवा रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स की पैकेजिंग पर इसे अनधिकृत रूप से एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक बताते हुए पाया था। एफडीए ने इस भ्रामक लेबलिंग के चलते 11.19 लाख रुपये मूल्य का स्टाक जब्त किया था, जिसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 का उल्लंघन बताया गया। एफडीए ने कंपनी को गलत लेबल वाली रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स को बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया था, लेकिन नियामक के अनुसार कंपनी ने इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया।

जम्मू कश्मीर में 2035 तक 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य, मौजूदा क्षमता से तीन गुना अधिक उत्पादन कर ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर जोर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2035 तक अपनी जलविद्युत उत्पादन क्षमता को मौजूदा क्षमता के तीन गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 11,000 मेगावाट तक पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से रखा गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने दिसंबर 2035 तक चालू जलविद्युत उत्पादन क्षमता को 10,969.65 मेगावाट तक ले जाने की व्यापक और समयबद्ध योजना तैयार की है। यह मौजूदा 3,540.15 मेगावाट की स्थापित क्षमता के तीन गुने से भी अधिक होगी, जिससे जम्मू-कश्मीर के बिजली परिदृश्य में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, बाहरी बिजली पर निर्भरता को कम करना और क्षेत्र के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए ठोस नींव तैयार करना है।

यूपीआई एमडीआर में हिस्सा चाहते हैं भुगतान एग्रीगेटर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर संसद से मिली हरी झंडी के बाद बढ़ी उम्मीदें

नई दिल्ली

भारत के भुगतान एग्रीगेटर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में सीधा और तय हिस्सा चाहते हैं। यह मांग तब उठी है जब हाल ही में संसद ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लगाने की अनुमति दी है। एग्रीगेटर अब इस शुल्क हिस्सेदारी के लिए साझेदार बैंकों पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपने परिचालन की लागत वसूलने में मदद मिल सके। सूत्रों के अनुसार देश में 50 से अधिक भुगतान एग्रीगेटर हैं, जिनमें एवेन्युजएआई, बिलडेस्क, रेजरपे, पेयू और फोनपे जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। ये सभी अब एमडीआर के तहत सीधे हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे उन्हें व्यापारियों को अपने प्लेटफार्म से जोड़ने (आनबोर्डिंग), उन्हें सेवाएं प्रदान करने और नए कारोबारियों को जोड़ने में आने वाली लागत को निकालने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, भुगतान एग्रीगेटर साझेदार बैंकों के माध्यम से शुल्क का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इस माडल से अब स्वतंत्र होना चाहते हैं।

एक प्रमुख भुगतान एग्रीगेटर के शीर्ष कार्यकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भुगतान एग्रीगेटर को एक निश्चित हिस्सा मिलना चाहिए और हम इसके लिए जोर-शोर से कोशिश करेंगे। हम शुल्क के बंटवारे के लिए संबंधित बैंकों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि उन्हें एक्वायरर (जो व्यवहार में बैंकों से आशय रखता है) की श्रेणी में शामिल न करके, शुल्क अर्जित करने वाले एक स्वतंत्र प्रतिभागी के रूप में मान्यता मिले। ऐसा होने पर उन्हें हर बार शुल्क साझेदारी के लिए अपने साझेदार बैंकों के साथ बातचीत नहीं करनी पड़ेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल भुगतान पर भविष्य में लगने वाला कोई भी शुल्क ग्राहक लेनदेन पर लागू नहीं होगा, बल्कि यह सिर्फ एक निश्चित सीमा से ज्यादा वाले मर्चेंट लेनदेन की सीमित श्रेणी पर लागू होगा। डिजिटल भुगतान उद्योग इस मुद्दे पर सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, सूत्रों का मानना है कि इस मांग का विरोध होने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि भुगतान एग्रीगेटर सीधे यूपीआई नेटवर्क के सदस्य नहीं हैं; वे प्रायोजक बैंकों के माध्यम से कारोबारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यूपीआई नेटवर्क का संचालन एनपीसीआई करता है और इसके सदस्य केवल बैंक होते हैं।

सेबी ने ईटीएफ नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा बढ़ाई, अब 7 सितंबर से प्रभावी होंगे नए प्रावधान

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है, जो अब 1 सितंबर 2026 के बजाय 7 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यह निर्णय शेयर बाजारों से मिले सुझावों और नियमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सेबी द्वारा जारी एक नए परिपत्र के अनुसार यह विस्तार ईटीएफ के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में काल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े नियमों पर लागू होगा। इन प्रावधानों को नियामक ने 15 जून 2026 को जारी एक पिछले परिपत्र में विस्तृत रूप से तय किया था। हालांकि, 15 जून के उस परिपत्र के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

टाटा संस को राहत, एजीएम के लिए साल के अंत तक का समय

नई दिल्ली

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए बड़ी राहत मिली है। कोरम पूरा न होने के कारण पहले स्थगित हुई एजीएम के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने अब तीन महीने की मोहलत दे दी है, जिससे कंपनी के पास 31 दिसंबर तक का समय है। यह निर्णय सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) पर लगी रोक के कारण पैदा हुई असाधारण स्थिति और टाटा संस के नेतृत्व में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय ने 27 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से यह मोहलत दी है। इससे पहले, कंपनी कानून के तहत एजीएम के लिए निर्धारित समय-सीमा 30 सितंबर थी। एजीएम के एजेंडे में चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार का मामला भी शामिल था, जिस पर पहली बैठक में चर्चा नहीं हो पाई थी। दरअसल, 18 अगस्त को होने वाली एजीएम को इसलिए टालना पड़ा था क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स की अहम हिस्सेदार सर रतन टाटा ट्रस्ट पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने रोक लगा दी थी। सर रतन टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और इस रोक के कारण एजीएम में अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं हो पाई। टाटा समूह के 100 साल से अधिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी होल्डिंग कंपनी की एजीएम स्थगित करनी पड़ी हो। चैरिटी कमिश्नर का यह आदेश महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट में हुए बदलाव के कथित उल्लंघन पर आया था। इस बदलाव के तहत ट्रस्ट के बोर्ड में हमेशा बने रहने वाले ट्रस्टियों (परपेचुअल ट्रस्टी) की संख्या कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। टाटा संस ने इसी असाधारण स्थिति का हवाला देते हुए मोहलत की अपील की थी। हालांकि, कंपनी रजिस्ट्रार ने मोहलत देते हुए टाटा संस को भविष्य में कंपनी अधिनियम के तहत सभी आवश्यक नियमों के अनुपालन में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। यदि सर रतन टाटा ट्रस्ट पर लगी रोक साल के आखिर तक जारी रहती है, तो आगे की कार्रवाई के लिए यह मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के पास जा सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार ने तीन महीने की मोहलत दी

जीएमआर का वैश्विक उड़ान लक्ष्य, भारतीय विमानन पर अटूट विश्वास

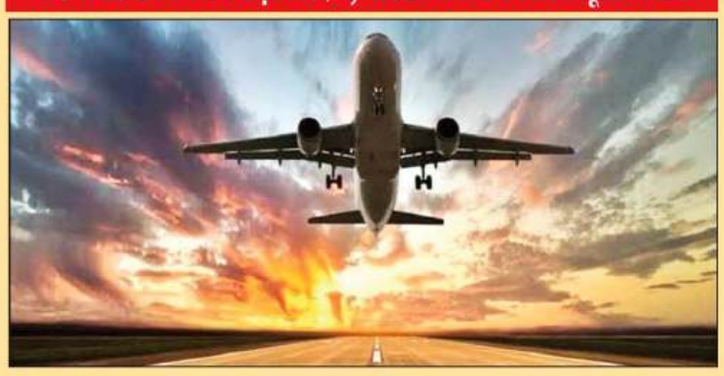

नई दिल्ली। जीएमआर समूह ने भारतीय विमानन क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि पर अपने प्रबल विश्वास को व्यक्त करते हुए वैश्विक विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। समूह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में हवाई अड्डों तथा उनसे जुड़े कारोबार में नए अवसर तलाशेगा। कंपनी के एक अ?धिकारी ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इन रणनीतिक पहलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जीएमआर वर्तमान में भारत में छह हवाई अड्डों (दिल्ली और हैदराबाद सहित) तथा इंडोनेशिया में एक हवाई अड्डे का संचालन करता है, जबकि यूनान में एक का विकास जारी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के भोगापुरम हवाई अड्डे ने 17 अगस्त से परिचालन शुरू किया है। राव ने बढ़ती आय, पर्यटन, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरकारी पहलों से भारतीय विमानन को दीर्घकालिक समर्थन मिलने पर जोर दिया। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी ने अपने एयरपोर्ट प्लेटफार्म कारोबार का विस्तार किया है, जिसमें शुल्क-मुक्त, मालवाहक, खुदरा और खाद्य-पेय जैसे कम पूंजी वाले व्यवसाय शामिल हैं। समूह नई रियायतों, परिचालन एवं रखरखाव अनुबंधों तथा हवाई अड्डों से जुड़े कम पूंजी वाले क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा।

वीआई ने लगातार चौथे महीने जोड़े नए ग्राहक, 20 करोड़ पहुंचा आंकड़ा

ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में 2.4 लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े

नई दिल्ली

दूरसंचार क्षेत्र में अपनी वापसी का संकेत देते हुए निजी क्षेत्र की कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) लगातार चौथे महीने नए ग्राहक जोड़ने में सफल रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह कंपनी के लिए एक सकारात्मक मोड़ है, खासकर वर्षों की ग्राहक हानि के बाद। जुलाई में 2,40,114 नए ग्राहक जुड़ने से कंपनी की कुल ग्राहक संख्या 19.90 करोड़ हो गई है, जो 20 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब है।

यह उपलब्धि वीआई के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 2018 में विलय के बाद कंपनी ने पहली बार किसी तिमाही (अप्रैल-जून वित्त वर्ष 2027) में शुद्ध नए ग्राहक जोड़े हैं। फरवरी से अब तक कंपनी ने 6.9 लाख से अधिक और अप्रैल से 5.7 लाख से अधिक ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं। यह पिछले साल के उस दौर से बिल्कुल अलग है, जब कंपनी ने छह महीनों में 36 लाख से अधिक ग्राहक खो दिए थे। आदित्य बिड़ला ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे एक अहम पड़ाव बताते हुए नेटवर्क ढांचे और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने में किए गए निरंतर निवेश का परिणाम बताया है। मुख्य कार्यकारी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में 15,500 और दो वर्षों में 32,000 4जी मोबाइल टावर एवं उपकरण लगाने से नेटवर्क में सुधार हुआ है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और उन्हें बनाए रखने की क्षमता बढ़ी है। किशोर के अनुसार, जिन क्षेत्रों में 5जी सेवा शुरू हुई है, वहां ग्राहकों के जुड़ाव में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है। वीआई ने पिछले वर्ष मार्च में दिल्ली से अपनी 5जी सेवा शुरू की थी और अगले दो तिमाहियों में 200 से अधिक शहरों में इसका विस्तार करने की योजना है। कंपनी ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्पाटीफाई के साथ साझेदारी और शैक्षिक पहल जैसे कई प्रयास किए हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बड़ा मसला सुलझने के बाद ही असली बदलाव आया है। भले ही वीआई अभी भी कुल ग्राहकों और 4जी/5जी उपभोक्ताओं के मामले में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से पीछे है, लेकिन यह लगातार वृद्धि कंपनी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है।

वैश्विक संकेतों से सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी

ब्याज दरों में वृद्धि की अटकलों ने दाम गिराए

नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख केविन वार्श द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत देने के बाद सोने का दाम 1 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया। इस गिरावट ने हाल की बढ़त को मिटा दिया, जिससे घरेलू बाजार में भी 10 ग्राम सोने की कीमत में 4100 रुपये से अधिक की कमी आई। एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 अगस्त को गोल्ड का रेट 4563.05 डालर प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गया, जो 25 अगस्त को दर्ज किए गए तीन महीने के उच्चतम स्तर 4696.18 डालर प्रति आउंस से काफी कम है। केविन वार्श के बयान के अलावा, अमेरिका के ताजा रोजगार से जुड़े कमजोर आंकड़े और स्ट्रेट आफ होर्मुज में बाधा के चलते कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी सोने के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर डाला। घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की रिपोर्ट के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 25 अगस्त को 162344 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 28 अगस्त को गिरकर 158226 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस प्रकार, तीन दिनों में 10 ग्राम सोने पर 4118 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। बुलियन मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड 156780 रुपये पर था, जिसमें 2830 रुपये या 1.770 प्रतिशत की कमी आई। सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी नरमी देखने को मिली। 25 अगस्त को 1 किलोग्राम चांदी 243446 रुपये थी, जो घटकर 240382 रुपये के स्तर पर आ गई। यानी चांदी की कीमत में 3064 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई।

इंडिगो वेंचर्स का एआई कंपनी सर्वम में रणनीतिक निवेश, परिचालन दक्षता पर जोर

नई दिल्ली। विमानन दिग्गज इंडिगो की कारपोरेट वेंचर कैपिटल इकाई इंडिगो वेंचर्स ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी सर्वम में रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। सीरीज-बी फंडिंग के तहत यह कदम विमानन परिचालन में एआई अनुप्रयोगों से दक्षता व ग्राहक अनुभव सुधारने के लिए उठाया गया है। हालांकि, निवेश राशि का खुलासा नही किया गया है। इंडिगो और सर्वम पहले से ही ग्राहक सेवा, कर्मचारियों की उत्पादकता और विमानन संचालन से जुड़े एआई ऐप्लिकेशन पर सहयोग कर रही हैं। इस निवेश के बाद दोनों कंपनियां इन ऐप्लिकेशन्स के विकास और परीक्षण जारी रखेंगी। सफल साबित होने वाले एआई समाधानों को इंडिगो के पूरे नेटवर्क में लागू किया जा सकता है, जिससे कंपनी के संचालन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। यह इंडिगो वेंचर्स का सार्वजनिक रूप से घोषित चौथा निवेश है, जो प्रौद्योगिकी और विमानन के भविष्य में उसके बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इससे पहले, वेंचर ने जुलाई 2025 में एरोस्पेस विनिर्माण कंपनी जेह एरोस्पेस में निवेश किया था। जनवरी 2026 में, इसने ट्रैवल एक्सेसरीज कंपनी एस्केप प्लान की 25 करोड़ डालर की सीरीज-ए फंडिंग में हिस्सा लिया और उसी महीने एयर-टैक्सी सेवाओं के लिए ईवीटीओएल विमान बनाने वाली सरला एविएशन में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

अश्विन बोले ऋषभ को अपनी शैली में सुधार की जरुरत

चेन्नई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर निशाना साधा है। अश्विन ने कहा है कि अति आक्रामकता दिखाने की जगह पर इस बल्लेबाज को मैच के हालातों के अनुसार खेलना चाहिये।

उन्होंने कहा कि इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने भले ही श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की है पर अभी भी उन्हें अपनी शैली में अधिक सुधार की जरुरत है। अश्विन ने ऋषभ के फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें केवल एक आक्रामक खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान बनाने की जगह पर देखना चाहिये कि खेल की वास्तविक जरुरतें क्या हैं।

अश्विन ने कहा कि उनका अभी का प्रदर्शन उस स्तर का नहीं है जैसा कि किसी स्थापित खिलाड़ी का होना चाहिये। श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैचों में कुल 168 रन और दो अर्धशतक बनाने के बाद भी उनके शाट चयन पर कई सवाल उठे हैं। अश्विन ने कहा, उनसे मेरी उम्मीदें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

अश्विन ने का कि उनकी शैली आक्रमक है पर उन्हें अपने अनुसार खेलने नहीं दिया जा सकता। साथ ही कहा कि टेस्ट क्रिकेट में मैच की स्थिति को बेहतर ढंग से समझना सबसे जरुरी है। विशेष रुप से तब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो।

उन्होंने सिडनी और ब्रिस्बेन में इस बल्लेबाज की यादगार पारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन मैचों को वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों के योगदान के बिना नहीं जीता जा सकता था। अश्विन ने आगाह किया, टेस्ट मैच बनाने और खेल के आखिरी सत्र में उसे जीतने के लिए 11 क्रिकेटरों की जरूरत होती है, लेकिन टेस्ट मैच हारने के लिए सिर्फ एक पल की बेवकूफी ही काफी होती है।

अश्विन का मुख्य तर्क यह है कि इस बल्लेबाज की प्रतिभा पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन वे उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही उनकी लगातार निर्णायक भूमिका तय करेगा। उन्होंने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उनके आक्रामक अंदाज की जांच-पड़ताल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ यादगार पारियां खेली हैं।

श्रीलंका दौरे पर इस बल्लेबाज को कोलंबो में लाहिरू कुमारा की गेंद से कलाई पर चोट लगने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा था, लेकिन दूसरे दिन क्रीज पर लौटते ही उन्होंने फिर आक्रामक खेल दिखाया। अश्विन का आग्रह है कि जब टीम को आक्रामक जोखिम के बजाय स्थिरता की जरूरत हो, तो उन्हें उसी अनुसार खेलना चाहिये।

न्यूज ब्रीफ

बायर्न म्यूनिख के साथ करार बढ़ाने की तैयारी में हैरी केन, क्लब के साथ शुरू हुई बातचीत

म्यूनिख। जर्मन फुटबाल क्लब बायर्न म्यूनिख के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने पुष्टि की कि उन्होंने क्लब के साथ अपने अनुबंध को बढ़ाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। केन का मौजूदा करार 2027 तक है। बुंडेसलीगा के मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख लंबे समय से केन के साथ करार आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर करता रहा है। क्लब की स्टटगार्ट के खिलाफ 5-1 की जीत के बाद केन ने बताया कि नए अनुबंध को लेकर पहली बैठक पिछले सप्ताह हुई थी। केन ने एक बयान में कहा, मैं 33 साल का हूं। संभवतः यह मेरा आखिरी अनुबंध नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए यह एक बड़ा अनुबंध होगा, जिस पर मुझे हस्ताक्षर करने हैं। उन्होंने कहा कि नए करार को लेकर अभी कई पहलुओं पर चर्चा की जानी बाकी है, लेकिन वह बायर्न के साथ अपना जुड़ाव जारी रखना चाहते हैं। केन 2023 में टोटेनहम हाटस्पर से बायर्न म्यूनिख पहुंचे थे। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे खुश हों। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे, जहां दोनों पक्ष खुश होंगे। 33 वर्षीय केन इस समय बैलन डीओर के दावेदारों में शामिल हैं। उन्होंने पिछले सत्र में बायर्न के लिए 31 बुंडेसलीगा मैचों में 36 गोल किए थे। यह जर्मन शीर्ष लीग के एक सत्र में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए तीसरे सबसे ज्यादा गोल थे। केन ने पिछले सत्र में बायर्न के साथ लीग और कप का खिताब भी जीता।

सीपीएल से जुड़ीं शिखा पांडे, यास्तिका भाटिया समेत चार भारतीय महिला क्रिकेटर

नई दिल्ली। चार भारतीय महिला क्रिकेटरों शिखा पांडे, यास्तिका भाटिया, पूजा वस्त्राकर और किरण नवगिरे ने आगामी कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध साइन किए हैं। टूर्नामेंट का आगामी सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा। अनुभवी तेज गेंदबाज शिखा पांडे और विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगी। 25 वर्षीय यास्तिका पहली बार कैरेबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगी, जबकि शिखा का यह टूर्नामेंट में तीसरा सत्र होगा। तेज गेंदबाजी आलराउंडर पूजा वस्त्राकर और आक्रामक बल्लेबाज किरण नवगिरे मौजूदा चैंपियन बारबाडोस ट्राइडेंट्स की ओर से मैदान पर उतरेंगी। दोनों खिलाड़ी पहली बार कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलेंगी। पूजा ने 2025 में लंबे समय तक चोट के कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद वापसी की थी। उन्होंने महिला प्रीमियर लीग में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद मध्य प्रदेश टी20 लीग में चंबल घड़ियाल्स की ओर से खेलीं।

टेस्ट और एकदिवसीय प्रारुप को बचाने सभी बोर्ड मिलकर प्रयास करें : चमिंडा वास

कोलंबो। पूर्व श्रीलंकाई तेज गेंदबाज चमिंडा वास ने क्रिकेट खेलने वाले सभी सदस्य देशों से टेस्ट और एकदिवसीय प्रारुप को बचाने की अपील की है। वास के अनुसर फ्रैंचाइजी क्रिकेट के इस दौर में टेस्ट और एकदिवसीय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वास ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और सभी राष्ट्रीय बोर्डों से टेस्ट तथा एक दिवसीय प्रारूपों के भविष्य को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। इससे पहले आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने भी कहा था कि प्रतिस्पर्धा की कमी वाली द्विपक्षीय श्रृंखलाओं का दौर अब समाप्त होना तय है। उसी के बाद से ही एकदिवसीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गयी हैं। वास ने माना है कि अब टी20 ही खेल का भविष्य है और अधिकतर देश इसे प्राथमिकता भी देना चाहेंगे पर इसके बाद भी सभी बोर्डों को यह समझना चाहिए कि टेस्ट और एकदिवसीय ही क्रिकेट के आधार हैं और इसी में किसी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। उन्होंने जोर दिया कि इन दोनों प्रारूपों को जीवित रखने के लिए ठोस कदम उठाना जरुरी है। इस अनुभवी गेंदबाज ने सभी क्रिकेट बोर्डों से इन पारंपरिक प्रारूपों को बचाये रखने करने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा है। वास के अनुसार, हमें 50 ओवर की क्रिकेट को जीवित रखने के लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था करनी होगी।

एशियाई खेलों में पदक का रंग बदलना चाहती हैं आशी चौकसे, बोलीं - हम अजेय होंगे

भोपाल

वर्ष 2018 में निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखने वाली भारतीय राइफल निशानेबाज आशी चौकसे अब अपने दूसरे एशियाई खेलों के लिए तैयार हैं। 24 वर्षीय आशी ने पिछले एशियाई खेलों में तीन पदक जीते थे और अब जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में अपने पिछले प्रदर्शन को स्वर्ण पदक में बदलने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी।

आशी ने 2022 एशियाई खेलों में, जो 2023 में आयोजित हुए थे, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते थे। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था।

पिछले एशियाई खेलों का अनुभव आशी के लिए आगामी प्रतियोगिता में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस स्तर की प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने की बेहतर समझ और आत्मविश्वास है।

आशी ने एक बयान में कहा, एशियाई खेल ओलंपिक के बाद सबसे बड़े बहु-खेल आयोजनों में से एक हैं और मैं पहले भी वहां हिस्सा ले चुकी हूं। मैंने उस मंच पर प्रदर्शन किया है और मुझे पता है कि वहां क्या करना होता है। तीन पदक जीतने के बाद अब मेरे पास इस स्तर पर खेलने का अच्छा अनुभव है। इसलिए इस बार मैं जापान स्पष्ट सोच और लक्ष्य के साथ जा रही हूं।

एशियाई खेलों की तैयारी के लिए भारतीय निशानेबाजी दल ने भोपाल में कई कड़े प्रशिक्षण शिविर लगाए। इन शिविरों में मुकाबले और फाइनल के अभ्यास के साथ खिलाड़ियों की सहनशक्ति और स्थिरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

आशी ने बताया, हमने तैयारी में काफी मेहनत की। शिविर में मुकाबलों और फाइनल का अभ्यास कराया गया। 10 दिन के शिविर में हमने तीन-चार मुकाबले और तीन-चार फाइनल खेले। 60 शाट का मुकाबला भी काफी गहन होता है। हमने 120 शाट का मुकाबला भी खेला, जो किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य लंबे समय तक हमारी सहनशक्ति और स्थिरता को परखना था।

भारतीय निशानेबाज खेल मनोवैज्ञानिकों के साथ भी काम कर रहे हैं और बायोफीडबैक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए खिलाड़ियों की सांस लेने की प्रक्रिया और निशाना लगाते समय शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश की जा रही है।

आशी ने कहा, मनोवैज्ञानिक तकनीक की मदद से निशाना लगाते समय हमारी सांस और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं पर नजर रखते हैं। हमने इसे कई बार आजमाया है और यह काफी मददगार रहा है। इससे हमें खुद को बेहतर समझने में मदद मिली है। हमें सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कुछ अभ्यास भी करने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि निशानेबाजी में छोटी-छोटी चीजें भी काफी मायने रखती हैं। हमें पता है कि क्या करना है और कैसे निशाना लगाना है, लेकिन कुछ छोटी चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से और लगभग पूर्णता के साथ कर लें, तो मुझे लगता है कि हम अजेय होंगे।

पिछले एशियाई खेलों के दबाव का अनुभव कर चुकीं आशी इस बार ज्यादा आत्मविश्वास और संयम के साथ उतरना चाहती हैं। उनका लक्ष्य साफ है— पिछली बार मिले पदकों का रंग बदलकर स्वर्ण पदक हासिल करना।

उन्होंने कहा, मैं इसे स्वर्ण पदक में बदलने को लेकर उत्साहित और पूरी तरह समर्पित हूं। मैं यह बहुत, बहुत ज्यादा चाहती हूं।

आशी चीन की मजबूत निशानेबाजी टीम के खिलाफ मुकाबले को लेकर भी उत्साहित हैं। पिछले एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत की सिफ्ट कौर समरा ने स्वर्ण और आशी ने कांस्य पदक जीता था, जबकि चीन की निशानेबाज को रजत पदक मिला था।

आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चीन की निशानेबाजी टीम के खिलाफ मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हूं। वे बहुत मजबूत टीम हैं। 2023 में हमने स्वर्ण और कांस्य जीता था और उन्हें अपने ही घर में रजत मिला था। हो सकता है कि वे अभी भी इसे याद कर रहे हों और बदला लेना चाह रहे हों। वे मजबूत टीम हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ मुकाबले को लेकर वास्तव में उत्साहित हूं।

स्कूल के एक शिविर में संयोग से पहली बार राइफल हाथ में लेने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज बनने तक आशी चौकसे का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने पहली बार एनसीसी शिविर में निशानेबाजी आजमाई थी और शुरुआती प्रदर्शन ने उन्हें इस खेल को करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनका चयन राज्य निशानेबाजी अकादमी में हुआ।

अब अपने दूसरे एशियाई खेलों में आशी अनुभव, कड़ी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी। उनका एकमात्र लक्ष्य पिछले एशियाई खेलों के पदक को इस बार स्वर्ण पदक में बदलना है।

सोनल दिनुशा के मुरीद हुए पुजारा, आने वाले समय में महान बल्लेबाज बनेंगे

मुंबई

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने श्रीलंकाई टीम के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा की जमकर प्रशंसा की है। पुजारा ने कहा है कि जिस प्रकार से सोनल खेलते है उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में वह महान बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। साथ ही कहा कि दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी देखकर दिग्गज बल्लेबाजों कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने की याद आ गयी।

दिनुशा ने कोलंबो में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की दोने ही पारियों में दबाव के बीच शतक लगाकर अपनी टीम को करारी हार से बचाया था। अंतिम दिन टीम के फालोआन खेलते समय जिस प्रकार से उन्होंने पूरे दिन बल्लेबाजी की उससे उनकी प्रतिभा का और कौशल का अंदाजा होता है। इस सीरीज में दिनुशा ने चार पारियों में 140.00 की प्रभावशाली औसत से कुल 420 रन बनाए, जिसमें तीन शानदार शतक और एक अर्धशतक शामिल था। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए, उन्होंने 722 गेंदों का सामना किया, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीरीज में खेली गई सबसे ज्यादा गेंदें हैं, जो उनकी धैर्यवान और दृढ़ बल्लेबाजी ताकत को दिखाती है।

पुजारा ने इस बल्लेबाज को लेकर कहा, पूरी सीरीज में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वह शानदार रही है। इससे मुझे कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने जैसे बल्लेबाजों के दौर की याद आ गयीहैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मैं उन श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानता था। मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 साल में सोनल श्रीलंकाई क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं। उन्होंने वह क्षमता दिखाई है।

दिनुशा के अब तक के करियर पर नजर डालें तो, उन्होंने पांच टेस्ट मैचों की नौ पारियों में 86.57 की प्रभावशाली औसत से 606 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर नाबाद 133 रन रहा है। वहीं, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी उनका रिकार्ड शानदार है; 70 मैचों में उन्होंने 48.44 की औसत से 4,118 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वोच्च स्कोर 145 है।

भारत के योहान बेंजामिन पुर्तगाली क्लब गुआर्डा एफसी से खेलते दिखेंगे

मुंबई। भारतीय फुटबालर योहान बेंजामिन के साथ पुर्तगाली क्लब गुआर्डा एफसी ने दो साल का करार किया है। इस करार से मिडफील्डर योहान को यूरोपीय फुटबाल में आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। 21 साल योहान अपने करियर में फुटबाल एकेडमी आफ बैंगलोर और मिनर्वा फुटबाल एकेडमी से जुड़े रहे हैं। इसके बाद वह शिलांग लाजोंग से खेलने लगे। यहां अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान ही योहान को क्लब की सीनियर और रिजर्व टीमों के साथ खेलने का अवसर मिला। उन्होंने 2024 शिलांग प्रीमियर लीग में 9 गोल कर अपनी टीम को खिताब जिताया था। साल 2023-24 एआईएफएफ यूथ लीग से वह सबसे नजरों में आये। इमसें उन्होंने 13 मैचों में 9 गोल किये जिससे उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम में जगह मिली। इसके बाद, उन्होंने 2025 सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में भारत की ओर से भाग लिया। वह अगस्त 2025 में स्लोवेनिया के एनएके ब्रावो क्लब की अंडर 19 टीम में शामिल हो गए।

5 सितंबर को डायमंड लीग फाइनल में नीरज पर रहेंगी नजरें , पथिरागे से मिलेगी टक्कर

ब्रसेल्स

भारत के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अब अगले माह पांच सितंबर को यहां होने वाले डायमंड लीग फाइनल में जीत दर्ज करने उतरेंगे। ऐसे में इस मुकाबले पर उनके प्रशंसकों की नजरें रहेंगी। नीरज ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। उन्होंने इस सीरीज की केवल दो प्रतियोगिताओं में ही भाग लेने के बाद भी 12 अंक हासिल कर अंक तालिका में छठा स्थान हासिल करते हुए शीर्ष छह में जगह बना ली है। अब फाइनल में उन्हें श्रीलंका के शीर्ष खिलाड़ी रुमेश पथिरागे से कड़ी टक्कर मिलना तय है। पथिरागे क्वालीफायर मुकाबले में सबसे अधिक अंक लेकर शीर्ष पर रहे थे।

नीरज की बात करें तो चोट से उबकर क्वालीफाई करना उनके लिए वापसी की तरह है। पिछले साल सितंबर से कमर के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण वह लंबे समय तक खेल से दूर थे।

इसके बाद दोहा डायमंड लीग में उनकी वापसी हुई, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। हाल ही में हुए ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में वह पूरी तरह फिट नहीं थे, फिर भी 85.83 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने रजत पदक जीता था। इसके बाद लुसाने डायमंड लीग में उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.05 मीटर का अच्छा थ्रो किया। गौरतलब है कि डायमंड लीग फाइनल चार और पांच सितंबर को ब्रसेल्स में होगा। इसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा पांच सितंबर को होगी, जिसमें कूद और थ्रो स्पर्धाओं के शीर्ष छह खिलाड़ी भाग लेंगे। इस फाइनल में सभी की नजरें नीरज के अलावा श्रीलंका के रुमेश पथिरागे पर होंगी, जो 39 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर हैं। इस श्रीलंकाई को डायमंड लीग ट्राफी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उन्होंने इस साल हुई पांचों भाला फेंक स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिनमें से वह चार में वे विजेता रहे और एक में दूसरे स्थान पर रहे। ज्यूरिख में उन्होंने 92.07 मीटर का शानदार थ्रो करके पहला स्थान

हासिल किया। ये इस सत्र में उनका दूसरा 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो था।

वहीं नीरज और पथिरागे के अलावा दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 35 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने ज्यूरिख में 86.93 मीटर का थ्रो किया। वह भी एक प्रबल दावेदार रहेंगे। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद एवं टोबैगो के केशोर्ण वालकाट 23 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। डायमंड लीग के अलावा, नीरज चोपड़ा पहली बार होने वाली विश्व एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई करने की राह पर हैं, जो 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 8 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और नीरज वर्तमान में सातवें स्थान पर हैं।

एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप के लिए चीन रवाना हुई भारतीय जूनियर हाकी टीम

नई दिल्ली

भारतीय जूनियर महिला हाकी टीम को एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए चीन के मोकी रवाना हो गई। प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 13 सितंबर तक होगा। 18 सदस्यीय भारतीय टीम की कमान मिडफील्डर खैदेम शिलैमा चानू संभालेंगी।

नवनियुक्त मुख्य कोच टिम व्हाइट के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के लिए लंबे समय तक तैयारी की है। टीम ने इस साल गर्मियों में ब्रिटेन का महत्वपूर्ण दौरा भी किया, जहां उसे शीर्ष स्तर कीओ टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव मिला।

5 से 14 जुलाई तक एडिनबर्ग और लिलेशल में हुए ब्रिटेन दौरे के दौरान भारत ने स्काटलैंड की सीनियर महिला टीम के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड और बेल्जियम की जूनियर टीमों के खिलाफ कुल सात मुकाबले खेले। भारत ने अमेरिका को 6-0 से हराया, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दो

मुकाबलों में 2-0 की जीत दर्ज की। अमेरिका के खिलाफ एक अन्य मुकाबला 1-1 से बराबर रहने के बाद भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत हासिल की।

इस दौरे से भारतीय टीम को स्काटलैंड की अनुभवी सीनियर टीम और बेल्जियम की मजबूत अंडर-21 टीम के खिलाफ खेलने का भी अहम अनुभव मिला।

रवाना होने से पहले मुख्य कोच टिम व्हाइट ने कहा, टीम एशिया कप के लिए चीन जाने को लेकर काफी उत्साहित है। हमारी तैयारी अच्छी रही है। हमने बेंगलुरु में आई इंडिया टीम के खिलाफ भी चार महत्वपूर्ण मुकाबले खेले। हमें भरोसा है कि हमने ऐसी रणनीति तैयार की है, जिसके खिलाफ खेलना विपक्षी टीमों के लिए मुश्किल होगा। अब हम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ इसे आजमाने के लिए उत्साहित हैं।

भारत को महिला वर्ग के एलीट पूल में मेजबान चीन, जापान, कोरिया और मलेशिया के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 सितंबर को कोरिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद 6 सितंबर को मलेशिया, 8 सितंबर को जापान और 9 सितंबर को मेजबान चीन से मुकाबला होगा।

भारत के एलीट पूल के मुकाबले :

- 5 सितंबर: भारत बनाम कोरिया — दोपहर 1 बजे
- 6 सितंबर: भारत बनाम मलेशिया — सुबह 9 बजे
- 8 सितंबर: जापान बनाम भारत — सुबह 11 बजे
- 9 सितंबर: चीन बनाम भारत — शाम 7 बजे

एलीट पूल में शीर्ष स्थान के लिए मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता नाकआउट चरण में प्रवेश करेगी। टूर्नामेंट का स्वर्ण पदक मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा।

एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप एशिया की शीर्ष जूनियर हाकी टीमों के लिए महत्वपूर्ण मंच है, जहां युवा खिलाड़ियों को महाद्वीप की मजबूत टीमों के खिलाफ अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलता है।

पढ़ाया जाएगा, कब और कितनी पिएं शराब

इटली के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को शराब पीने का पाठ पढ़ाया जाएगा। छात्रों को यह साप्ताहिक क्लास दी जाएगी, जिसमें उन्हें यह बताया जाएगा कि शराब कितनी मात्रा में पी जानी चाहिए। इस क्लास में छह साल तक की उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस क्लास में बताया जाएगा कि आखिर हमें कितनी शराब पीनी चाहिए ताकी हम बेकाबू न होने पाएं। इस तरह की पढ़ाई के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया जाना है, जिसमें इटली की संस्कृति को बचाए रखने पर जोर

दिया जाएगा। इस बिल का नॉर्दन इटली के ब्रेस्सिया में पहले ही अनुपालन हो रहा है। यहां बच्चों के देश में शराब के योगदान के बारे में बताया जा रहा है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत स्थानीय राजनीतिज्ञों ने की है। इस साल गर्मियों से ही इसे पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। इस संसदीय विधेयक को लाने की योजना बनाने वाले डारियो स्टेफानो ने कहा कि बच्चों को इस बारे में बताया जाएगा कि देश में शराब का क्या योगदान है और इसे कैसे बनाया जाता है।

बेकार नहीं हैं नींबू के छिलके

नींबू के फायदों के बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन, क्या आप नींबू के छिलकों के फायदों और पोषक गुणों के बारे में जानते हैं। नींबू के छिलके में कैल्शियम और विटामिन सी होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह हड्डियों से जुड़ीं बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, रहेयूमेटॉयड अर्थराइटिस और इंफ्लेमेटरी पोलीअर्थराइटिस से भी बचाने में मदद करता है।

शरीर में ज्यादा आयरन से होते हैं ये रोग

कई बार लोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने से बहुत अधिक मात्रा में आयरन का सेवन करने लगते हैं। जिससे शरीर में आयरन अधिक की मात्रा हो जाती है। क्या आपको मालुम है शरीर में आयरन की अती होने से शरीर खतरनाक बीमारियों का घर बन जाता है। इन खतरनाक बीमारियों के बारे में जानते हैं।

आयरन की अधिकता

शरीर में आयरन की कमी से बाल झड़ने व एनीमिया रोग की समस्या पैदा होती है। इसी कारण आयरन शरीर के लिए काफी जरूरी माना जाता है। एक इंसान को फिट और हेल्दी रहने के लिए रोज 21 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। लेकिन क्या आपको मालुम है की शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से भी कई सारी बीमारियां होती हैं।

दिल की बीमारियां

आयरन की अधिकता का सबसे ज्यादा असर दिल पर पड़ता है और इससे दिल की अनेक तरह की समस्या उत्पन्न होती है। शरीर में आयरन की अधिकता होने से दिल के टिश्यू ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाते हैं। कई बार टिश्यू ऑक्सीडेटिव डैमेज इतना हो जाता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है।

लीवर डैमेज

कई बार आयरन की अती होने से लीवर भी डैमेज हो जाता है। किसी इंसान के शरीर में अगर आयरन की मात्रा बढ़ती है तो लीवर में प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे लीवर के टिश्यू का ऑक्सीकरण सही से नहीं हो पाता और वो डैमेज होने लगते हैं। कई बार लीवर के कैंसर का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है।

कैंसर

शरीर में आयरन की अधिक मात्रा होने से कई बार कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शरीर में आयरन सही से फिल्टर नहीं होने के कारण होता है। जिसकी वजह से शरीर में टॉक्सिन और फ्री रैडिकल बढ़ जाते हैं, जो कि कैंसर का कारक होते हैं।

ऑस्टियोपोरोसिस

आयरन की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं तो आयरन की अती से भी हड्डियों के कमजोर होने की संभावना रहती है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार, शरीर में आयरन की अधिक मात्रा से हड्डियों के गठन और कैल्शियम के अवशोषण की हड्डी से जड़े ऑक्सीडेशन व एंटी-ऑक्सीडेशन तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति में शरीर का लंबे समय तक रहने से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है।

बुढ़ापे में बीमारियों से बचाएगा टीकाकरण

बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही उसे बीमारियों से बचाए रखने के लिए पूरे साल न जाने कितने टीके लगवाए जाते हैं। ताकि साल भर वे हेल्दी और स्वस्थ रह सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा बुजुर्गों के लिए भी जरूरी हो गया है। जी हां, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद या आपके माता-पिता रोग मुक्त जीवन जीएं, तो उनके लिए टीकाकरण जरूरी है।

यह टीका हर साल होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाने में बेहद मदद करता है। आज भी 50 फीसदी वरिष्ठ नागरिकों को इस टीकाकरण और इसे न लगवाने पर होने वाले नुकसानों के बारे में जानकारी नहीं है। आप जो बोते हैं, वही काटते हैं- यह एक पुरानी कहावत है। यह हमारी सेहत पर भी उतनी ही लागू होती है। जब हम युवा होते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान न रखने से होने वाले नुकसानों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। कई बार हम यह भी सोचते हैं कि एक बार टीका लेना काफी है। लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इस टीकाकरण का असर कम होने लगता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जाती है। इस वजह से युवाओं के मुकाबले बड़ी उम्र वालों में रोकी जा सकने वाली बीमारियां होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।

उन्होंने कहा, अगर वह पहले से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे कि दिल की बीमारियां, हाईपरटेंशन, डायबिटीज या ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमनरी डिजीज से जुड़ जाती हैं तो यह जानलेवा साबित हो सकता हैं। आम तौर पर होने वाली बीमारियां फ्लू, हैपेटाइटिस-ए, हैपेटाइटिस-बी होती हैं। इन हालतों को देखते हुए कुछ टीका 65 साल की उम्र के बाद देनी जरूरी हो जाता है। बच्चों को चाहिए कि उनके अभिभावक यह टीका लें ताकि वह लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी सकें।

इन बातों का रखें ध्यान

- फ्लू वैक्सीन 6 महीने या उससे बड़े सभी व्यक्तियों को देने की सलाह दी जाती है।
- निमूनिया वैक्सीन 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को दी जानी चाहिए।
- टेटनस टॉक्साईड हर 10 साल बाद देते रहना चाहिए।
- अगर पहले ना लगी हो तो सभी को हैपेटाइटिस-बी की वैक्सीन देनी चाहिए।
- 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले को डायबिटीज है तो उन्हें हैपेटाइटिस-बी की वैक्सीन देनी चाहिए। आगे चल कर ब्लड ग्लूकोज की मॉनीटरिंग की अधिक आवश्यकता के लिए यह वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है।

जानिए प्लास्टिक बोतल के नीचे लिखे नंबर का मतलब

अगर आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर, वॉटर बॉटल्स या प्लास्टिक पैकेज्ड प्रोडक्ट को उल्टा करेंगी तो आप पाएंगी कि नीचे एक छोटा सा ट्राइएंगल है और इसमें एक नंबर या अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिखे होते हैं। दरअसल यह नंबर या अक्षर उन कैमिकल्स के बारे में बताता है, जो उस विशेष प्लास्टिक प्रॉडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है...

पॉलीएथीलीन टेरेफथैलेट: यह प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आप इसे कोल्ड ड्रिंक या वॉटर वॉटल्स के नीचे पाएंगी। यह प्लास्टिक केवल एक बार इस्तेमाल के लिए ही बनी होती है। पैट प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि अगर आप इसे साबुन या डिटर्जेंट की मदद से साफ करती हैं या अधिक तापमान पर रखती हैं तो संभव है कि प्लास्टिक में मिले केमिकल्स पानी के साथ मिल जाएं। ये केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। इन बोतलों को दोबारा इस्तेमाल न करें।

हाई डेंसिटी पॉलीएथीलीन: यह प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनी होती है और ज्यादातर प्लास्टिक बैग, ऑयल बॉटल्स, जूस बॉटल्स, मक्खन या योगर्ट टब्स बनाने में इस्तेमाल होती है। यह प्लास्टिक हार्ड और अपारदर्शी होती है और उच्च तापमान पर भी अप्रभावित रहती है। यह हानिकारक केमिकल्स नहीं निकालती और दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग दर सभी प्लास्टिक में सबसे ज्यादा है।

विनायल या पीवीसी : यह थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और अक्सर डिटर्जेंट और विंडो क्लीनर बॉटल्स में पाया जाता है। जिन बॉटल्स पर पीवीसी या 3वी लिखा होता है, वे बहुत नुकसान करती हैं और आपको उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बॉटल्स हानिकारक केमिकल्स निकालती हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्लास्टिक को रीसाइकल भी नहीं किया जाता।

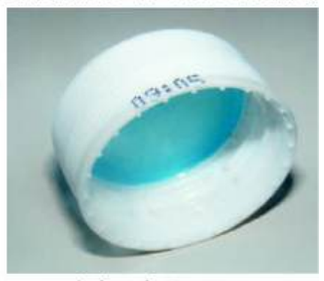

लो डेंसिटी पॉलीएथीलीन: यह थर्मोप्लास्टिक भी पेट्रोलियम से बनी होती है और या तो अपारदर्शी होती है या फिर पारभासी। इसका इस्तेमाल शॉपिंग बैग्स, फूड रैप्स और ब्रेड बैग्स बनाने में होता है। यह प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है क्योंकि इससे कोई हानिकारक पदार्थ या केमिकल नहीं निकलता।

पॉलीप्रॉपाइलीन: पॉलीप्रॉपाइलीन या पीपी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। यह कठोर, मजबूत होता है और इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। इसलिए इसे सबसे सुरक्षित प्लास्टिक माना गया है। पीपी साइन दवाइयों की शीशी, केचप या अन्य दबाने वाली बॉटल्स में पाया जा सकता है। इस प्लास्टिक को रीसाइकल भी किया जाता है।

पॉलीस्टाइरीन: पी एस भी एक पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक है, जिसे इंसुलेशन और पैकेजिंग मटैरियल्स में इस्तेमाल किया जाता है। आप इस साइन को डिस्पोजेबल कंटेनर्स या एग कार्टन्स में देख सकती हैं। प्लास्टिक के इस रूप को रीसाइकल करना बहुत ही मुश्किल है।

पॉलीकार्बोनेट: यह प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह बीपीए केमिकल्स छोड़ता है। इसका इस्तेमाल फूड कंटेनर्स और तीन से पांच गैलन की वॉटर बॉटल्स बनाने में होता है। यह रीसाइकल भी नहीं किया जा सकता।

लौकी के जूस में शहद मिलाएं और फिर देखिए जादू

क्या आप जानते हैं कि लौकी के जूस में शहद मिला कर पीने से आपको 7 तरह की बीमारियों से निजात मिल सकती है? इस जूस को बनाना काफी आसान है, बस ताजी लौकी के कुछ फ्रेश पीस को ब्लेंडर में डालिए और उसके साथ 1 चम्मच शहद मिलाइए। फिर इसे ब्लेंड कीजिए और यह जूस पीने के लिए तैयार हो जाएगा। जूस बनाने से पहले लौकी के छोटे पीस को जरुर चखना चाहिए, अगर यह तीखी है तो इसका जूस ना बनाएं। तो आइए अब जानते हैं इसके 7 स्वास्थ्य लाभ क्या हैं-

पाचन शक्ति बढ़ाए- अगर रह रह कर आपको एसिडिटी और कब्ज की समस्या रहती है, तो लौकी का जूस पिएं। इससे पेट में एसिड का लेवल न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस जूस को पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट जल्दी बर्न होता है।

यूटीआई ठीक करे- मूत्र पथ संक्रमण की समस्या इस जूस के नियमित सेवन से ठीक होती है। यह यूरीने से एसिड के लेवल को कम करता है। इसे पीने से नसें चौड़ी हो जाती हैं जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है।

प्रेगनेंसी में जरूर पिएं- लौकी तथा शहद, दोंनो ही चीजों में विटामिन, कैल्शियम और फोलेट पाए जाते हैं, जिससे हर प्रेगनेंट महिला को पीना चाहिए। **किसी भी उपाय को करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।**

सही संतुलन, अनुपात, रंग और स्वाद का ध्यान रखना जरूरी

बिना सोचे-समझे न खाएं सलाद

हम सब जानते हैं कि एक कटोरी भर सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, परंतु सही संतुलन, अनुपात, रंग और स्वाद कैसे प्राप्त किया जाए यह एक प्रमुख प्रश्न है जो हमें भयभीत करता रहता है। इसलिए जरूरी ये है कि हम सलाद का सेवन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे किस अनुपात में खाना है। आज हम आपको बताते हैं सलाद के बारे में कुछ बुनियादी बातें।

मीठे के स्थान पर कर सकते हैं सेवन

बहस लगातार जारी है कि आपको सलाद का सेवन कब करना चाहिए। भोजन से पहले या बाद में। यदि मुख्य भोजन के बाद सलाद का सेवन किया जाए तो ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा मीठे के स्थान पर सलाद का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होता है।

इससे बनेगी रुचि

काबुली चने तथा अन्य अंकुरित खाद्यों को एक तरफ रखकर प्रति सप्ताह सलाद में कुछ नया शामिल करें। ताजा जड़ी-बूटियों, चुकंदर के टुकड़ों, एवेकाडो, कम फैट वाला, गोट्य चीज या ताकत से भरपूर कद्दू के बीजों का सेवन करें। ये न सिर्फ आपकी सलाद में रुचि बनाए रखेंगे, बल्कि कुछ अलग पोषक तत्व और स्वाद भी आपके सलाद में शामिल करेंगे।

इसमें विटामिंस ज्यादा

हरे रंग के सभी सलाद स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। आइसबर्ग लैट्यूस सलाद की प्लेट में आकर्षक और कुरकुरा तो लगता है, परंतु पोषण के मामले में यह बहुत बढ़िया नहीं होता। इसकी बजाय गहरे रंग वाले पत्तों का सेवन करें जैसे पालक, राकेट लीव्स, रैड एंड ग्रीन लीफ, तथा रोमेन लैट्यूस को सलाद में शामिल करें। इनमें विटामिन्स मिनरल्स अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं।

क्रंच से बचें...

क्रिस्पी नूडल्स या क्रन्च (ब्रैड के कुरमुरे टुकड़े) को अपने थाई या एशियाई सलाद चाहे आपको अत्यधिक स्वादिष्ट लगता हो, परंतु यह आपकी कमर के लिए ठीक नहीं है। क्रूटन्स को प्रोसैस्ड व्हाइट ब्रेड से तैयार किया जाता है जिसका अर्थ है खाली कार्बोहाइड्रेट्स तथा कैलोरीज की अधिकता जिस प्रकार का क्रंच आप चाहते हैं उसके लिए अखरोट या सिंघाड़ों का सेवन बढ़िया रहता है।

ऑफिस में तनाव व काम के दबाव से मुक्ति पाएं

अच्छी व छोटी-सी नींद तनाव व काम के दबाव से मुक्ति दिलाती है क्योंकि नींद के दौरान क्षतिग्रस्त कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं। यदि आप काम के बीच थोड़ी-सी नींद लेते हैं तो इससे आपकी याददाश्त तेज होती है और बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है।

अक्सर आफिस के किसी कर्मचारी को सोते देख उसके बॉस की भौंहें तन जाती हैं और वह उसकी मेज पर जोर से हाथ मारते हैं ताकि कर्मचारी जागकर अपने काम पर लग सकें। ऐसे लोग बॉस की नजरों में लापरवाह होते हैं पर ऐसा जरूरी नहीं। न्यूयार्क में हुए नए शोध बताते हैं कि यदि आप काम के बीच थोड़ी-सी नींद लेते हैं तो इससे आपकी याददाश्त तेज होती है और बुद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। अध्ययन में स्वैच्छिक कर्मचारियों को 2 वर्गों में बांटा गया व उन्हें शब्द दिए गए। थोड़ी देर बाद एक वर्ग ने 47 मिनट की नींद ली व दूसरे ग्रुप ने पत्रिका पढ़ कर व फिल्में देख कर यह समय व्यतीत किया। जब 6 घंटों बाद उन दोनों का दोबारा टेस्ट लिया गया तो पाया गया कि जिन लोगों ने नींद ली थी उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से याद कर लिए थे। दूसरे वर्ग की बजाय उन्होंने 15 प्रतिशत अधिक शब्दों को याद किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक अच्छी व छोटी-सी नींद तनाव व काम के दबाव से मुक्ति दिलाती है क्योंकि नींद के दौरान क्षतिग्रस्त कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती हैं इसलिए व्यक्ति की याद करने की क्षमता पुनः तीव्र हो जाती है।

मैनेजमैंट टिप्स: बड़े विचारों को सरलता से पकड़ें...

अच्छे विचारों को लिखने और उनसे फायदा उठाने के लिए अपनी स्मृति या ब्लैकबेरी पर भरोसा न करें। पुराने जमाने के लोगों की तरह 3 गुणा 5 के इंडैक्स काड्र्स का उपयोग करें। उन्हें अपने साथ जेब में रखें और जब भी कोई अच्छा विचार सुनें तो उसे एक कार्ड पर लिख लें। भौतिक रूप से कार्ड साथ रखने का नतीजा होगा कि आप हर शाम को उन पर विचार करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसके अलावा विचारों को लिखने के कार्य से उन्हें याद रखने और आत्मसात करने में भी मदद मिलती है। साथ ही जेब में खाली कार्ड होने से आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको नए विचारों की तलाश करनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनना है।

रेसिपी

कोर्न करी

सामग्री

11/2 कप उबले हुए मीठी मकई के दानें, 2 स्पून तेल, 2 दालचीनी टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 स्पून कोर्नफ्लार , 2 कप नारीयल दुध मे घुला, नमक स्वादअनुसार। **हरा पेस्ट बनाने के लिये:** 11/2 कप हरा धनिया, 1/4 कप प्याज, 2 स्पून ताज़ा कसा हुआ नारीयल, 7 लहसुन की कलियां, 2 अदरक के टुकड़े, 4 स्पून खसखस, 6 हरी मिर्च,1 स्पून नींबू का रस, **परोसने के लिए:** रोटी/पराठे,स्टीम्ड चावल

विधि

कढ़ाई मे तेल गरम करें, तैयार हरा पेस्ट, दालचीनी, लौंग और इलायची डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट भूने। मीठे मकई के दाने डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर लगातार हिलाते हुए, 1 मिनट तक पकाएं। कोर्नफ्लार-नारीयल के दुध का मिश्रण और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मध्यम आंच पर लगातार हिलाते हुए, 5 से 6 मिनट तक पकाएं। रोटी या पराठे और चावल के साथ गरमा गरम परोसें।

उड़द दाल विथ पनीर

सामग्री

3/4 कप उड़द दाल, 1/2 कप छोटे पनीर के टुकड़े, 1/2 टी-स्पून हल्दी, नमक , स्वाद अनुसार, 1 टी-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज़, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टी-स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया

विधि

एक गहरे बर्तन में उड़द दाल को पर्याप्त पानी का उपयोग करते हुए 1 घंटा पहले भिगोए और अच्छे से छान लीजिए। प्रेशर कुकर में उड़द दाल, 1/4 टी-स्पून हल्दी, नमक और 1 1/4 कप पानी डालिए, अच्छे से मिलाइए और 1 सिटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाइए। ढककन खोलने से पहले भांप को निकल जाने दीजिए। छानिए और एक तरफ रख दीजिए। एक नॉन-स्टिक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमे पनीर डालिए और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट या पनीर का हल्का भूरा रंग होने तक भूनिए। आंच पर से हटाए और एक तरफ रख दीजिए। उसी कढ़ाई में जीरा डालिए। जब जीरा चटखने लगे, उसमे प्याज़ डालिए और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट भूनिए। उसमे टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, बचा हुआ 1/4 टी-स्पून हल्दी, 2 टेबल-स्पून पानी और नमक डालिए, अच्छे से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 मिनट, बीच-बीच में हिलाते हुए पकाइए। उसमे पकाई हुई उड़द दाल डालकर, हल्के से मिलाइए और मध्यम आंच पर 2 मिनट पकाइए। उसमे भुना हुआ पनीर और धनिया डालकर, हल्के से मिलाइए और मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट ओर, बीच-बीच में हिलाते हुए पकाइए। गरमा गरम परोसिए।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**